उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

सामान्य अध्ययन

VOLUME-2

भारतीय संविधान

एवं

राज्यव्यवस्था

अध्यायवार सॉल्व्ड पेपर्स

प्रधान सम्पादक
आनन्द कुमार महाजन

सम्पादन एवं संकलन
यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स PCS परीक्षा विशेषज्ञ समिति

कम्प्यूटर ग्राफिक्स
बालकृष्ण एवं विनय साहू

सम्पादकीय कार्यालय
यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स
12, चर्च लेन, प्रयागराज-211002
मो. : 9415650134
Email : yctap12@gmail.com
website : www.yctbooks.com

प्रकाशन घोषणा
प्रधान सम्पादक एवं प्रकाशक आनन्द कुमार महाजन ने प्रिंटेक्स इण्डिया, प्रयागराज से मुद्रित करवाकर, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स, 12, चर्च लेन, प्रयागराज के लिए प्रकाशित किया।

इस पुस्तक को प्रकाशित करने में सम्पादक एवं प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरती गई है फिर भी किसी त्रुटि के लिए आपका सुझाव एवं सहयोग सादर अपेक्षित है।

किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज होगा।

मूल्य : 295/-

विषय-सूची

भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था

भाग-1 : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पूर्व परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्न-पत्रों का विश्लेषण चार्ट 4-6
- भारत का संवैधानिक विकास (Constitutional Development of India) 7-12
- संविधान सभा का गठन, कार्य प्रणाली एवं विभिन्न समितियाँ (The Making of the Constitutional Assembly, its Function and Related Committees) 13-16
- संविधान पर विदेशी प्रभाव (Foreign Effects on Constitution) 17-18
- संविधान की प्रस्तावना/उद्देशिका-विषय वस्तु एवं महत्त्व (Preamble of the Constitution - Subject & its Importance) 19-23
- संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची एवं विभिन्न भाग (Articles, Schedule & Parts of the Constitution) 24-40
- संघ एवं इसका राज्यक्षेत्र (The Union & its Territory) 41-43

भाग-2 : संविधान के मूल तत्त्व

- नागरिकता (Citizenship) 44-45
- मूल अधिकार (Fundamental Rights) 45-57
- राज्य के नीति निदेशक तत्त्व (Directive Principles of State Policy) 58-63
- मूल कर्त्तव्य (Fundamental Duties) 64-66

भाग-3 : सरकार की शासन प्रणाली

- संसदीय व्यवस्था (Parliamentary System) 67-71
- संघीय व्यवस्था (Federal System) 72-76
- केन्द्र-राज्य सम्बंध (Centre-State Relations) 77-79
- अंतर्राज्यीय सम्बंध (Inter-State Relations) 79-80
- आपातकालीन उपबंध (Emergency Provisions) 81-83

भाग-4 : संसद

- संरचना एवं कार्यप्रणाली (Structure & Its Function) 84-91
- राष्ट्रपति (President) 92-105
- उपराष्ट्रपति (Vice-President) 105-107
- लोक सभा (Loksabha) 108-116
- राज्य सभा (Rajya Sabha) 117-122
- प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद (Prime Minister & Council of Ministers) 123-127
- संसदीय समितियाँ एवं विभिन्न प्रस्ताव (Parliamentary Committees) 127-131
- विभिन्न संविधान संशोधन एवं उसकी प्रक्रिया (Various Constitutional Amendments and its Procedure) 132-140
- वरीयता अनुक्रम (Sequence of Precedence/Seniority) 141-141

भाग-5 : राज्य सरकार की संरचना एवं कार्यप्रणाली

- राज्यपाल/उपराज्यपाल (Governor/Lieutenant Governor) 142-145
- राज्य विधानमंडल (State Legislature) 146-148
- मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद (Chief Minister and Council of Ministers) 148-149
- कुछ राज्यों हेतु विशिष्ट उपबंध (Special Provisions of some States) 149-150

भाग-6 : न्यायपालिका

- उच्चतम न्यायालय-गठन, शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार
  (Supreme Court- Establishment, Empowerment & Jurisdiction) 151-159
- उच्च न्यायालय-गठन, शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार
  (High Court-Establishment, Empowerment and Jurisdiction) 159-161
- अधीनस्थ न्यायालय एवं प्राधिकरण (Subordinate Court and Tribunals) 161-161

भाग-7 : स्थानीय शासन

- पंचायती राज का विकास एवं संरचना (Development & Structure of Panchayatiraj) 162-172
- नगरीय शासन (Urban Government) 173-175

भाग-8 : संवैधानिक निकाय

- निर्वाचन आयोग (Election Commission) 176-178
- वित्त आयोग (Finance Commission) 179-180
- भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (Comptoller and Auditor General of India) 181-181
- संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग (Union and State Public Service Commission) 182-183
- अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु राष्ट्रीय आयोग
  (National Commission for Scheduled Castes & Scheduled Tribes) 184-184
- भारत का महान्यायवादी एवं राज्य का महाधिवक्ता
  (The Attorney General of India & The Advocate General of State) 185-186
- राजभाषा एवं लोक सेवाएँ (State Language & Public Services) 187-187

भाग-9 : गैर संवैधानिक निकाय

- योजना आयोग/नीति आयोग (Planning Commission/Niti Commission) 188-189
- राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council) 189-189
- राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग (National & State Human Right Commission) 190-191
- लोकपाल एवं लोकायुक्त (Lokpal and Lokayukta) 191-191
- विभिन्न महत्वपूर्ण आयोग (Various Important Commission) 192-193

भाग-10 : राजनीतिक गतिशीलता

- राजनीतिक दलों का गठन एवं मान्यता (Structure and Affiliation of Political Parties) 194-195
- दल बदल कानून (Law of Defection) 196-196
- विविध (Miscellaneous) 197-208

प्रश्न-पत्रों का विश्लेषण

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पूर्व परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्न-पत्रों का विश्लेषण चार्ट

क्र.	परीक्षा का नाम एवं परीक्षा वर्ष	कुल परीक्षा प्रश्न
	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग	
A.	**U.P. P.C.S. (Pre)**	
	वर्ष 1991-1997	8 × 120 = 960
	वर्ष 1998-**2022**	25 × 150 = 3750
	वर्ष 2004 Spl., 2008 Spl., 2015 पुनर्परीक्षा	3 × 150 = 450
B.	**U.P. P.C.S. (Mains)**	
	वर्ष 2002-2016 (2002, 2003 में 1-1 प्रश्न-पत्र तथा 2004-2017 में 2-2 प्रश्न-पत्र)	30 × 150 = 4500
	वर्ष 2004 Spl., 2008 Spl. (प्रत्येक के दो प्रश्न-पत्र)	4 × 150 = 600
C.	**U.P. UDA/LDA/RO/ARO (Pre & Mains) Exam.**	
	U.P. UDA/LDA (Pre) 2001	1 × 150 = 150
	U.P. UDA/LDA (Pre) 2006	1 × 100 = 100
	U.P. RO/ARO (Pre) 2010	1 × 120 = 120
	U.P. RO/ARO (Pre) 2010 Spl.	1 × 140 = 140
	U.P. RO/ARO (Pre) 2013	1 × 140 = 140
	U.P. RO/ARO (Pre) 2014	1 × 140 = 140
	U.P. RO/ARO (Pre) 2016 (निरस्त)	1 × 140 = 140
	U.P. RO/ARO (Pre) 2017	1 × 140 = 140
	U.P. RO/ARO (Pre) Re-exam 2016	1 × 140 = 140
	U.P. RO/ARO (Pre) 2021	1 × 140 = 140
	U.P. RO/ARO (Mains) 2010	1 × 120 = 120
	U.P. RO/ARO (Mains) 2010 Spl.	1 × 120 = 120
	U.P. RO/ARO (Mains) 2013	1 × 120 = 120
	U.P. RO/ARO (Mains) 2014	1 × 120 = 120
	U.P. RO/ARO (Mains) 2017	1 × 120 = 120
	U.P. RO/ARO (Mains) 2016 (2020)	1 × 120 = 120
	U.P. RO/ARO (Mains) 2021	1 × 120 = 120

D.	**U.P. Lower Subordinate (Pre & Mains) Exam.**	
	U.P. Lower Subordinate (Pre) 1998	1 × 100 = 100
	U.P. Lower Subordinate (Pre) 2002	1 × 100 = 100
	U.P. Lower Subordinate (Pre) 2002 Spl.	1 × 100 = 100
	U.P. Lower Subordinate (Pre) 2003	1 × 100 = 100
	U.P. Lower Subordinate (Pre) 2004	1 × 100 = 100
	U.P. Lower Subordinate (Pre) 2004 Spl.	1 × 100 = 100
	U.P. Lower Subordinate (Pre) 2008	1 × 100 = 100
	U.P. Lower Subordinate (Pre) 2009	1 × 100 = 100
	U.P. Lower Subordinate (Pre) 2013	1 × 150 = 150
	U.P. Lower Subordinate (Pre) 2015	1 × 150 = 150
	U.P. Lower Subordinate (Mains) 2013	1 × 120 = 120
	U.P. Lower Subordinate (Mains) 2015	1 × 120 = 120
E.	**U.P.P.S.C. राजस्व निरीक्षक (प्री.) परीक्षा 2014**	1 × 100 = 100
F.	**U.P.P.S.C. वन संरक्षक अधिकारी परीक्षा**	
	उत्तर प्रदेश वन संरक्षक परीक्षा 2013	3 × 150 = 450
	उत्तर प्रदेश वन संरक्षक परीक्षा 2015	3 × 150 = 450
	उत्तर प्रदेश वन संरक्षक परीक्षा 2017	3 × 150 = 450
	उत्तर प्रदेश वन संरक्षक परीक्षा 2018, 2019, 2020, 2021	8 × 150 = 1200
G.	**U.P. PSC खाद्य सुरक्षा अधिनियम परीक्षा, 2013**	1 × 75 = 75
H.	**U.P. PSC खाद्य एवं सफाई निरीक्षक परीक्षा, 2013**	1 × 50 = 50
	U.P.P.S.C. स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी परीक्षा, 2006	1 × 150 = 150
	U.P.P.S.C. कर निरीक्षक अधिकारी परीक्षा, 2003 U.P.P.S.C. कर निरीक्षक अधिकारी परीक्षा, 1997	1 × 150 = 150 1 × 100 = 100
	U.P.P.S.C. सहायक अभियंता परीक्षा, 2004, 2007, 2007(II), 2008, 2011, 2013 U.P.P.S.C. सहायक अभियंता परीक्षा, 2019, 2021	6 × 100 = 600 2 × 25 = 50
	U.P.P.S.C. खण्ड शिक्षा अधिकारी (BEO) परीक्षा, 2019	1 × 120 = 120
	UPPSC BEO Re-Exam, 2006 PART-I (Exam Date : 04.07.2009)	1 × 100 = 100
	UPPSC BEO Re-Exam, 2006 PART-II (Exam Date : 04.07.2009)	1 × 100 = 100
	UPPSC SDI Exam 2006 PART-I (Exam Date : 27.07.2008)	1 × 100 = 100
	UPPSC SDI Exam 2006 PART-II (Exam Date : 27.07.2008)	1 × 100 = 100
	UPPSC SDI Exam 2003 (Exam Date : 15.11.2005)	1 × 75 = 75
	UPPSC यूनानी स्वास्थ्य अधिकारी परीक्षा, 2016 (Exam Date : 22.01.2020) UPPSC यूनानी स्वास्थ्य अधिकारी परीक्षा, 2018 (Exam Date : 25.07.2021)	1 × 30 = 30 1 × 30 = 30
	UPPSC GDC प्रवक्ता परीक्षा, 2020 (15-03-2022)	1 × 40 = 40
	UPPSC GDC प्रवक्ता परीक्षा, 2017 (3-11-2019)	1 × 30 = 30
	UPPSC GDC प्रवक्ता परीक्षा, 2013 (27-12-2014)	1 × 30 = 30

	UPPSC सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा, 2014 (11-11-2018)	1 × 30 = 30
	UPPSC ADO परीक्षा, 2014	1 × 30 = 30
	UPPSC मेडिकल ऑफिसर परीक्षा, 2021 (31.07.2022)	1 × 30 = 30
	UPPSC मेडिकल ऑफिसर परीक्षा, 2018 (30-09-2018)	1 × 30 = 30
	UPPSC डायट (DIET) प्रवक्ता परीक्षा, 2014 (15-03-2015)	1 × 30 = 30
	UPPSC GIC प्रवक्ता परीक्षा, 2021 (19-09-2021)	1 × 40 = 40
	UPPSC GIC प्रवक्ता परीक्षा, 2017 (23-09-2018)	1 × 30 = 30
	UPPSC GIC एल.टी.ग्रेड भर्ती परीक्षा, 2018 (29-07-2018)	1 × 30 = 30
	UPPSC GIC प्रवक्ता परीक्षा (शि.वि.), 2015 (25-09-2016)	1 × 30 = 30
	UPPSC GIC प्रवक्ता परीक्षा, 2015 (15-09-2015)	1 × 30 = 30
	UPPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर परीक्षा, 2020 (22-03-2022)	1 × 25 = 25
	UPPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर परीक्षा, 2020 (12-12-2021)	1 × 25 = 25
	UPPSC आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा, 2021 (26-09-2021)	1 × 40 = 40
	UPPSC आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा, 2015 (04-10-2015)	1 × 30 = 30
	UPPSC GIC प्रवक्ता परीक्षा, 2012 (14-06-2015)	1 × 30 = 30
	UPPSC आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा, 2012 (02-06-2015)	1 × 30 = 30
	UPPSC GIC प्रवक्ता परीक्षा, 2009 (22-05-2015)	1 × 30 = 30
	UPPSC आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा, 2009 (12-05-2015)	1 × 30 = 30
	UPPSC राज्य कृषि सेवा परीक्षा, 2020 (01-08-2021)	1 × 40 = 40
	UPPSC स्टॉफ नर्स परीक्षा, 2017, 2021 (03-10-2021), 2022 (10.04.2022)	3 × 30 = 90
	UPPSC विधिक्षण अधिकारी परीक्षा, 2020	1 × 40 = 40
	UPPSC APS परीक्षा, 2007, 2013	2 × 100 = 200
	UPPSC पशु चिकित्सा अधिकारी परीक्षा, 2020 (15.05.2022)	1 × 30 = 30
	UPPSC सहायक रेडियो अधिकारी परीक्षा, 2018 (28.08.2022)	1 × 30 = 30
	UPPSC कम्प्यूटर सहायक परीक्षा, 2019 (23.08.2020)	1 × 25 = 25
	UPPSC सहायक प्रबंधक (गैर तकनीकी) परीक्षा, 2016 (22.11.2020)	1 × 100 = 100
	वैकल्पिक विषय (Optional Subject) के सामान्य अध्ययन सम्बन्धी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न	
	उत्तर प्रदेश पी.सी.एस. (राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल एवं अन्य) (प्री) परीक्षा 1990-2011	96×120 = 11520
	कुल प्रश्न-पत्र = 264	**30907**

नोट- उपरोक्त प्रश्न-पत्रों के सम्यक विश्लेषण के उपरान्त यथा संभव समान प्रकृति एवं प्रवृत्ति से बचते हुए **भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था** से सम्बन्धित कुल **3478** प्रश्नों को अध्यायवार प्रस्तुत किया गया है। दुहराव वाले प्रश्नों का परीक्षा वर्ष एवं परीक्षा नाम यथास्थान निर्दिष्ट कर दिया गया है ताकि प्रश्न पूछने की तकनीकि का प्रतियोगियों को लाभ मिल सके।

01.

भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

Indian Constitution & Polity : Historical Background

1. भारत का संवैधानिक विकास
(Constitutional Development of India)

1. किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने 'अखिल भारतीय संघ' प्रस्तावित किया था?

(a) इंडियन कौंसिल अधिनियम, 1892
(b) भारत सरकार अधिनियम, 1909
(c) भारत सरकार अधिनियम, 1919
(d) भारत सरकार अधिनियम, 1935

उत्तर–(d) **RAS/RTS (Pre.) Opt. Pol Science 2010**
UPPCS (Mains) G.S. II[nd] Paper 2012
UPUDA/LDA (Pre.) G.S. 2010
UPPCS (Pre) Opt. Pol. Sci. 2009, 2008, 2005
U.P. PSC Kanoongo Exam. 2015
UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 1992
UPPCS (Mains) G.S. II[nd] Paper 2013

व्याख्या–भारत सरकार अधिनियम-1935 में कुल 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं–

- केन्द्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गयी।
- एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था। जिसका निर्माण ब्रिटिश भारत के प्रान्तों, चीफ कमिश्नर प्रान्तों तथा देशी रियासतों से मिलकर बनना था लेकिन लागू नहीं हो सकी क्योंकि देशी रियासतों का संघ में शामिल होना वैकल्पिक था, अनिवार्य नहीं।
- प्रान्तों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रान्तीय स्वायतता की व्यवस्था की गई। जो 1937 में लागू हुई।
- प्रान्तीय विधानमण्डलों का विस्तार किया गया। प्रान्तों में 11 में से 6 विधानमण्डलों में द्विसदनीय व्यवस्था की गयी। केन्द्रीय विधानमण्डल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गयी।
- प्रान्तों में मताधिकार का विस्तार किया गया। साम्प्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ाकर इसे हरिजनों तक विस्तृत किया गया।
- वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया।
- एक संघीय न्यायालय (1937 में) एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की व्यवस्था की गयी।
- शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों में किया गया-(क) संघ सूची (ख) राज्य सूची और (ग) समवर्ती सूची
- अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास थीं।

2. भारतीय शासन अधिनियम, 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थीं?

(a) संघीय विधान-मण्डल को
(b) गवर्नर जनरल को
(c) प्रांतीय विधान-मण्डल को
(d) प्रांतीय राज्यपालों को

उत्तर (b) **UPPCS (Mains) G.S. II[nd] 2008**
(UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 2005)

व्याख्या– उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

3. निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गयी थी?

(a) भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
(b) भारत सरकार अधिनियम, 1909
(c) भारत सरकार अधिनियम, 1919
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर–(d) **UPPCS (Pre.) G.S., 2014**

व्याख्या– उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

4. निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ?

(a) इण्डियन कौन्सिल्स ऐक्ट, 1909
(b) गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट, 1919
(c) गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट, 1935
(d) इण्डियन इनडिपेन्डेन्स ऐक्ट, 1947

उत्तर–(c) **UPPCS (Mains) G.S. II[nd] Paper 2011**

व्याख्या– उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

5. 1935 के अधिनियम में उल्लिखित था :

(a) प्रांतीय स्वायत्तता (b) साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व
(c) संघीय व्यवस्था (d) a, b और c सत्य हैं

उत्तर : (d) **UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 1992**

व्याख्या– उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

6. भारत सरकार अधिनियम, 1919 आधारित था

(a) मार्ले-मिण्टो सुधार पर
(b) मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर
(c) रैम्से मैक्डोनाल्ड अवार्ड पर
(d) नेहरू रिपोर्ट पर

उत्तर : (b) **UPPSC ADO 2014**

व्याख्या–भारत सरकार अधिनियम, 1919 को मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट (सुधार) के नाम से भी जानते हैं।
मॉण्टेग्यू भारत सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे।

7. संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ?

(a) 9 दिसम्बर 1946 (b) 16 अगस्त 1947
(c) 26 जनवरी 1948 (d) 26 नवम्बर 1946

उत्तर : (a) **UPPSC APS 2010**

व्याख्या–संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसम्बर, 1946 ई. को नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के वरिष्ठतम् सदस्य डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।

8. गवर्नर-जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया?

(a) 1773 का रेग्यूलेटिंग अधिनियम
(b) पिट्स इण्डिया अधिनियम, 1784
(c) भारतीय परिषद् अधिनियम, 1861
(d) चार्टर अधिनियम, 1793

उत्तर : (a) **UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 1998**

व्याख्या- 1773 के रेग्यूलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गर्वनर को बंगाल का गवर्नर-जनरल बना दिया गया था। इस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। ध्यातव्य है कि 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। लार्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल (1833 के एक्ट के तहत) थे।

9. बंगाल का गवर्नर-जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया

(a) सन् 1813 चार्टर अधिनियम द्वारा
(b) सन् 1833 चार्टर अधिनियम द्वारा
(c) सन् 1909 के अधिनियम द्वारा
(d) सन् 1919 के अधिनियम द्वारा

उत्तर- (b) **UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 2006**

व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

10. किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गयी?

(a) रेग्युलेटिंग एक्ट 1773
(b) भारतीय परिषद अधिनियम 1861
(c) भारत सरकार अधिनियम 1935
(d) भारतीय संविधान 1950

उत्तर : (a) **UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 1999**
UPPCS (Mains) 2010

व्याख्या- भारत में सर्वप्रथम रेग्यूलेटिंग अधिनियम, 1773 द्वारा कलकत्ता (बंगाल) में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी।

11. मार्ले-मिन्टो सुधार 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन नहीं है?

(a) विधान परिषदों के आकार में वृद्धि
(b) केन्द्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत
(c) साम्प्रदायिक और पृथक् निर्वाचन पद्धति।
(d) केन्द्रीय विधान परिषद् में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं

उत्तर–(d) **UPPCS (Pre) Opt. Political Science 2010**

व्याख्या– मार्ले-मिन्टो सुधार 1909 के अंतर्गत केन्द्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान प्राप्त था, जिनकी संख्या बढ़ाकर 16 से 60 कर दी गई।

12. निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व सम्बन्धी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके–

(a) 1773 का रेग्यूलेटिंग अधिनियम
(b) 1784 का पिट्स इण्डिया अधिनियम
(c) 1833 का चार्ट्र अधिनियम
(d) 1858 का भारत सरकार अधिनियम

उत्तर-(b) **UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science, 2002**

व्याख्या - 1784 पिट्स इण्डिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल (नियंत्रण बोर्ड) नामक एक नये निकाय का गठन किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी दीवानी, सैनिक और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करें। इस अधिनियम ने प्रशासनिक सुविधा के लिए कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया।

13. ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए एक लाख रुपये दिए थे?

(a) वुड्स का डिसपैच, 1854
(b) चार्टर अधिनियम, 1813
(c) चार्टर अधिनियम, 1853
(d) भारतीय परिषद अधिनियम, 1892

उत्तर : (b) **UPPCS (Mains) G.S. IInd Paper 2009**

व्याख्या–1813 के चार्टर ऐक्ट में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह एक लाख रुपये भारतीय 'साहित्य के पुनरूत्थान और स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा विज्ञान की उन्नति के लिए खर्च करें।'

14. निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद् में एक विधि-सदस्य की अभिवृद्धि हुई–

(a) मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, 1919
(b) भारत सरकार अधिनियम, 1935
(c) भारत परिषद् अधिनियम, 1861
(d) चार्टर अधिनियम, 1833

उत्तर : (d) **UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 1999**

व्याख्या- चार्टर अधिनियम, 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्य- कारिणी में एक नए कानूनी सदस्य की वृद्धि की गई तथा वह कानूनी सदस्य (Law Member) लॉर्ड मैकाले था।

15. कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया :

(a) 1833 (b) 1831

(c) 1861 (d) None of these/कोई नहीं

उत्तर : (d) UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 1993

व्याख्या : 1773 के रेग्यूलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री 'पीट द पंगर' ने 1784 में ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करवाया जिसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के रूप में जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा पहली बार 'ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश' शब्द का प्रयोग किया गया साथ ही कंपनी के वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया।

16. किस अधिनियम ने पहली बार भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया?

(a) चार्टर एक्ट 1833

(b) चार्टर एक्ट 1853

(c) गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858

(d) इंडियन कौंसिल एक्ट 1861

उत्तर–(d) UPPCS (Pre) 2012

UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 1997

व्याख्या– इंडियन कौंसिल एक्ट 1861 (भारत परिषद अधिनियम, 1861) के द्वारा वायसराय कैनिंग द्वारा कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

17. 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी :

(a) गवर्नर-जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया

(b) प्रांतों को स्थानीय विषयों के संबंध में कानून निर्माण का अधिकार दिया गया

(c) उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई

(d) उपरोक्त सभी सत्य हैं

उत्तर : (a) UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 1992

व्याख्या- 1861 के अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे–

1. इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरूआत हुई। 1862 में लार्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया।
2. इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरूआत की। किन्तु सभी प्रान्तों को यह अधिकार नहीं दिया गया था।
3. बंगाल, उत्तर - पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ।
4. इसके तहत भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में की गई। 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में हुई।

18. गवर्नर-जनरल परिषद् में वृद्धि करके पहली बार एक अलग विधायी मशीनरी निर्मित की गयी–

(a) भारत-परिषद् अधिनियम, 1861 द्वारा

(b) चार्टर अधिनियम, 1853 द्वारा

(c) सुधार अधिनियम, 1909 द्वारा

(d) भारत परिषद् अधिनियम, 1892 द्वारा

उत्तर : (b) (UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 1999)

व्याख्या–चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा पहली बार गर्वनर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया।

19. निम्नलिखित में से 'भारतीय स्वतन्त्रताओं का अधिकार पत्र' किसे कहा जाता है?

(a) रेग्यूलेटिंग एक्ट, 1773

(b) पिट्स इंडिया एक्ट, 1784

(c) चार्टर एक्ट, 1813

(d) महारानी की घोषणा, 1858

उत्तर–(d) (UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 2011)

व्याख्या–1858 के भारत शासन अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे।

1. गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। लार्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे।
2. एक नए पद, भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। इसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी।
3. भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। यह एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया।

20. निम्नांकित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारम्भ हुई थीं?

(a) चार्टर अधिनियम - 1853

(b) भारत सरकार अधिनियम - 1858

(c) भारत परिषद अधिनियम - 1861

(d) भारत परिषद अधिनियम - 1892

उत्तर–(c) (UPPCS (Pre) Opt. Spl. Pol. Sci. 1994, 1999, 2006, 2008)

व्याख्या – भारत परिषद अधिनियम, 1861 से ही संवैधानिक विकास के दौरान संसदीय प्रणाली का सूत्रपात माना जाता है। ज्ञातव्य है कि इस अधिनियम द्वारा `कार्यकारिणी परिषद' में विधायी कार्यों के लिए कुछ गैर-सरकारी सदस्यों के लिए स्थान सुरक्षित किया गया। यहीं से भारत में पहली बार प्रतिनिधि संस्थाओं का शुभारम्भ हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल, उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ।

21. निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार साम्प्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली का आरम्भ किया-

(a) भारत सरकार अधिनियम, 1909
(b) भारत सरकार अधिनियम, 1919
(c) भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
(d) भारतीय परिषद अधिनियम, 1862

उत्तर (a) UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science, 2008, 2001 UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 1998, 1990

व्याख्या- भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909 (मिंटो-मार्ले सुधार) द्वारा भारत में सर्वप्रथम साम्प्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली प्रारम्भ की गई।

22. भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया-

(a) 1909 के अधिनियम के अन्तर्गत
(b) 1919 के अधिनियम के अन्तर्गत
(c) 1935 के अधिनियम के अन्तर्गत
(d) 1947 के अधिनियम के अन्तर्गत

उत्तर-(b) UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 2001, 1990 UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science, 1991, 94

व्याख्या-1919 के अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया और अब तक भारत सचिव द्वारा किये जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया।
इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे-

1. इसने प्रान्तों में द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारम्भ की।
2. इस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था (राज्यपरिषद एवं विधानसभा) का गठन किया गया।
3. वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से (कमांडर-इन-चीफ को छोड़कर) तीन सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था।
4. इसने सांप्रदायिक आधार पर सिक्खों, भारतीय ईसाईयों, आंग्ल-भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धान्त को विस्तारित कर दिया।
5. इस कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया।
6. इसके तहत 1926 में सिविल सेवको की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया।
7. इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया।
8. इसके अंतर्गत 1927 में (साइमन आयोग) का गठन किया गया। यह आयोग 1928 में भारत आया था। इसका कार्य दस वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था।

23. केंद्र में कौन-सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया?

(a) 1961 ऐक्ट (b) 1917 ऐक्ट
(c) 1919 ऐक्ट (d) 1915 ऐक्ट

उत्तर – (c) **UPPCS (Mains) G.S. II[nd] Paper 2008 UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 2005**

व्याख्या – उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

24. मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड प्रस्ताव, 1919 की क्या प्रमुख अनुशंसा थी?

(a) प्रांतीय शासन पर जन सामान्य का सीमित नियंत्रण
(b) प्रांतीय विधान-सभा को पूर्ण शक्ति
(c) शक्ति का अधिकतम विकेन्द्रीकरण
(d) केन्द्र में कोई भी उत्तरदायी सरकार नहीं

उत्तर : (a) **(UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 1997)**

व्याख्या- उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

25. 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थीं :

(a) प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए
(b) स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाएगा
(c) a और b दोनों सही हैं
(d) उपरोक्त सभी गलत हैं

उत्तर : (c) **(UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 1992)**

व्याख्या— 1919 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य- प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाना तथा स्वशासन की संस्थाओं का विकास करना था, अर्थात् उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। प्रशासन में भारतीयों के सम्पर्क के अन्तर्गत वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से (कमांडर-इन-चीफ़ को छोड़कर) तीन सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था।

26. 20 अगस्त, 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है-

(a) मांटेग्यू घोषणा के नाम से
(b) मोर्ले घोषणा के नाम से
(c) मिन्टो घोषणा के नाम से
(d) चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से

उत्तर–(a) (UPPCS (Pre) Opt. Political Science 2008)

व्याख्या – 20 अगस्त 1917 के सुधारों को माण्टेग्यू सुधार के नाम से जाना जाता है। मांटेग्यू ने 20 अगस्त, 1917 को कामन सभा से अंग्रेजी सरकार के उद्देश्य पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा - ''महामहिम सम्राट की सरकार की नीति, जिससे भारत सरकार भी पूर्णतः सहमत है, यह है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का सम्पर्क उत्तरोत्तर बढ़े तथा स्वशासी प्रशासनिक संस्थाओं का धीरे-धीरे विकास हो जिससे अधिकाधिक प्रगति करते हुए उत्तरदायी प्रणाली भारत में स्थापित हो और यह अंग्रेजी साम्राज्य के विभिन्न अंग के रूप में आगे बढ़े।''

27. निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है?

(a) भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट (1928) ने समर्थन किया था
(b) भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था
(c) अगस्त प्रस्ताव, 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे
(d) क्रिप्स मिशन, 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था

उत्तर : (a) (UPPCS (Mains) G.S. II[nd] Paper 2009) (UPPCS (Pre) Opt. Political Science 2009)

व्याख्या – सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा नियुक्त नेहरू समिति (1928) ने जिस भावी संविधान के स्वरूप की संस्तुति की थी उसमें मौलिक अधिकार निहित थे। सन् 1946 में कैबिनेट मिशन ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की लिखित गारंटी देना आवश्यक है। कैबिनेट मिशन ने अन्य बातों के साथ-साथ मौलिक अधिकारों पर भी रिपोर्ट देने के लिए एक सलाहकार समिति के गठन की सिफारिश की।

28. निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम, 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्त्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है?

(a) देश के लिए लिखित संविधान
(b) विधान मंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि
(c) एक संघ की योजना पर विचार
(d) विधान मंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित (nominate) किया जाना।

उत्तर–(a) **UPPCS (Mains) G.S. II[nd] Paper 2010**

व्याख्या– देश को एक लिखित संविधान देने का विचार सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन में किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय रियासतों की एक 'अखिल भारतीय संघ' की परिकल्पना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाए गए। वे विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। विधान मंडल में कुछ सरकारी सदस्यों का मनोनयन भी इस अधिनियम की विशेषता थी।

29. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट 1935 को किसने ''दासता का एक नया अधिकार पत्र'' कहा था?

(a) महात्मा गांधी (b) जवाहरलाल नेहरू
(c) सरदार पटेल (d) राजेन्द्र प्रसाद

उत्तर (b)

UPPSC Food & Sanitary Inspector Exam, 2013

व्याख्या- पं. जवाहरलाल नेहरू ने इसे, 'दासता का नया अधिकार पत्र' और 'अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी' संविधान की संज्ञा दी। जिन्ना ने इसे ''पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बतलाया''। क्रिप्स मिशन को उत्तरतिथीय चेक की संज्ञा गाँधी जी ने दी थी।

30. ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम कब पारित किया था?

(a) जनवरी 1947 में (b) जून 1947 में
(c) जुलाई 1947 में (d) अगस्त 1947 में

उत्तर – (c) **UPPCS (Mains) G.S. II[nd] Paper 2012**

UPPSC Food & Sanitary Inspector Exam, 2013

व्याख्या – भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया जिसे 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया और सम्राट के हस्ताक्षर के पश्चात उसी दिन से यह अधिनियम प्रवर्तन में आ गया था।

31. भारतीय संविधान के वृहद् होने के कारण हैं–

(a) इनमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है
(b) इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है
(c) यह एक बड़े देश के शासन से सम्बन्धित है
(d) इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है

उत्तर–(*) **UPPCS (Pre.) G.S., 1997**

व्याख्या–भारतीय संविधान के बृहद होने में किसी एक कारण को मानना युक्तिसंगत नही है। विभिन्न देशों के संविधानों से प्राप्त अनुभव, अनेक प्रावधानों की स्पष्टता के लिए विस्तृत प्रशासकीय निरूपण, देश की विशालता और जटिल समस्याओं के निराकरण के लिए विस्तृत प्रावधानों का उल्लेख तथा संघ और इकाईयों के लिए अलग-अलग संविधान न होकर एक ही संविधान होना, इत्यादि कारण भारतीय संविधान को विश्व का सबसे विशाल संविधान बनाते हैं।

32. पं. जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में अन्तरिम सरकार का गठन कब हुआ था?

(a) जुलाई, 1946 में (b) अगस्त, 1946 में
(c) सितम्बर, 1946 में (d) अक्टूबर, 1946 में

उत्तर–(c) **UPPCS (Mains) G.S.-II[nd] 2006**

व्याख्या – 2 सितम्बर, 1946 को पंडित जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें प्रारम्भ में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी, किन्तु बाद में 26 अक्टूबर, 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल करते हुए अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया।

33. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए –

सूची-I	**सूची-II**
A. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909	1. द्विशासन पद्धति का आरम्भ
B. भारत शासन अधिनियम, 1935	2. 1916
C. लखनऊ समझौता	3. लार्ड मिन्टो
D. भारत शासन अधिनियम, 1919	4. प्रान्तीय स्वायत्तता

कूट :

	A	**B**	**C**	**D**		**A**	**B**	**C**	**D**
(a)	1	2	3	4	(b)	4	3	2	1
(c)	2	4	1	3	(d)	3	4	2	1

उत्तर–(d) **UP-UDA/LDA Special (Mains) G.S., 2010**

व्याख्या – भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 मिन्टो-मार्ले सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम, 1935 द्वारा बाह्य रूप से प्रान्तों को स्वायत्तता दी गई थी परन्तु वास्तव में समस्त कार्यकारी शक्तियाँ गवर्नर के पास थीं। लखनऊ समझौता 1916 में काँग्रेस तथा मुस्लिम लीग में हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतो में द्विशासन पद्धति का आरम्भ हुआ।

34. एक नये संविधान के अंतर्गत भारत को सम्प्रभुता सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया?

(a) इसी दिन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी
(b) इसी दिन 1919 में जलियाँवाला बाग त्रासदी घटित हुई थी

(c) इसी दिन 1930 में काँग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया था
(d) इसी दिन 1942 में महात्मा गाँधी ने भारत छोड़ो आन्दोलन प्रारम्भ किया था

उत्तर– (c) **UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 2009**

व्याख्या– भारत को सम्प्रभुता सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन (दिसम्बर 1929) में पारित हुए संकल्प के आधार पर 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था।

35. माउण्ट बेटन योजना आधार बनी -
(a) ब्रिटिश शासन की निरंतरता का
(b) सत्ता के हस्तांतरण का
(c) देश के विभाजन का
(d) साम्प्रदायिक समस्या के निदान का

उत्तर – (c) **UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 2008**

व्याख्या– 3 जून 1947 को लार्ड माउंट बेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की जिसमें दोनों डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए देश के विभाजन को आवश्यक माना गया।

36. सूची I तथा सूची II को सुमेलित कीजिए तथा नीचे कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए–

सूची I (अधिनियम)	सूची II (प्रमुख प्रावधान)
A. भारतीय परिषद् अधिनियम-1892	1. द्विसदनात्मक केन्द्रीय व्यवस्थापिका
B. भारतीय परिषद् अधिनियम-1909	2. केन्द्र में द्वैध शासन
C. भारत सरकार अधिनियम-1919	3. व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार
D. भारत सरकार अधिनियम-1935	4. प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर-सरकारी बहुमत

कूट :
(a) A-4, B-3, C-1, D-2 (b) A-3, B-4, C-1, D-2
(c) A-2, B-4, C-3, D-1 (d) A-1, B-3, C-4, D-2

उत्तर : (b) **UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 1999**

व्याख्या- सुमेल इस प्रकार है– (A) भारतीय परिषद् अधिनियम 1892 – (3) व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार, (B) भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909— (4) प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर-सैरकारी बहुमत, (C) भारत सरकार अधिनियम, 1919– (1) द्विसदनात्मक केन्द्रीय व्यवस्थापिका, (D) भारत सरकार अधिनियम, 1935– (2) केन्द्र में द्वैध शासन।

37. नीचे दो वक्तव्य दिए हैं :
कथन (A) : भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है।
कारण (R) : इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है।
उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सत्य है?
(a) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है
(b) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, परन्तु (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(c) (A) सही है, परन्तु (R) असत्य है
(d) (A) असत्य है, परन्तु (R) सही है

उत्तर–(b) **UPPCS (Mains) Spl. G.S. IInd 2008**

व्याख्या–भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान के मूल स्रोत विदेशों के संविधान से ग्रहण किये गये है। जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, जर्मनी, कनाडा एवं सोवियत संघ के संविधान प्रमुख है।

38. भारत सरकार अधिनियम, 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ, क्योंकि:
(a) निर्धारित संख्या में 'देशी राज्य' संघ में शामिल नहीं हुए
(b) भारतीय राजनैतिक दलों ने उसका विरोध किया
(c) वायसराय ने उसके पुनर्विलोकन की संस्तुति की
(d) ब्रिटिश सरकार ने उसे लागू न करने का निर्णय लिया

उत्तर–(a) **UPPCS Tax Inspector Exam 1997**

व्याख्या– भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह अधिकथित शामिल था कि आधे राज्य संघ में शामिल होने के लिए सहमत होते तो, भारत को एक संघ बनाया जा सकता है। भारत सरकार अधिनियम, 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ क्योंकि निर्धारित संख्या में देशी रियासतों ने संघ में शामिल होने से इंकार कर दिया।

39. भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था
(a) जनवरी 22, 1946 को (b) जनवरी 22, 1947 को
(c) फरवरी 20, 1947 को (d) जुलाई 26, 1946 को

उत्तर–(b) **UPPCS BEO GS 2006**

व्याख्या– 13 दिसम्बर 1946 को पं. जवाहर लाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया।

40. भारत
1. एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है।
2. एक प्रतिनिधिक लोकतंत्र है।
3. एक लोकतांत्रिक समाज है।
4. समाजवाद से बंधा हुआ है।
नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए:
कूट:
(a) 1 और 2 (b) 1, 2 और 4
(c) 2, 3 और 4 (d) सभी चारों

उत्तर–(d) **UP PSC GIC 2008**

व्याख्या– भारत एक लोकतांत्रिक एवं प्रतिनिधिक लोकतंत्र है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात करता है। लोकतांत्रिक आधारित व्यवस्था में भारत एक लोकतांत्रिक समाज में परिणत हुआ है।

2. संविधान सभा का गठन, कार्य प्रणाली एवं विभिन्न समितियाँ
(The Making of the Constitutional Assembly, its Function and Related Committees)

1. भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था?

(a) डा. बी. आर. अम्बेडकर (b) डा. राजेन्द्र प्रसाद
(c) श्री बी. एन. राव (d) डा. के. एम. मुंशी

UPPSC Poly. Lecturer 2021

Ans.(c) : भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता श्री बी. एन. राव थे। सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किन्तु 11 दिसम्बर, 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष तथा बी. एन. राव को संवैधानिक परामर्शदाता नियुक्त किया गया।

2. कांस्टिट्यून्ट असेम्बली के अध्यक्ष थे-

(a) डॉ. बी.आर. अंबेडकर **(b)** डॉ. के.एन. काटजू
(c) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद **(d)** सी. राजगोपालाचारी

उत्तर (c) **U.P. P.C.S., 1998, 2000**

व्याख्या- उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

3. निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिये।

I. प्रारूप समिति की नियुक्ति
II. भारतीय संविधान पारित हुआ
III. भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि
IV. संविधान सभा की पहली बैठक
नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।

(a) III, II, I, IV (b) IV, I, III, II
(c) I, II, IV, III (d) IV, I, II, III

उत्तर : (d) **UPPSC Staff Nurse 2021**

व्याख्या–घटनाओं का सही कालक्रम इस प्रकार है–

संविधान सभा की पहली बैठक	- 9 दिसम्बर, 1946
प्रारूप समिति की नियुक्ति	- 29 अगस्त, 1947
भारतीय संविधान पारित हुआ	- 26 नवम्बर, 1949
भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि	- 26 जनवरी, 1950

4. 1946 में गठित संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(a) सभी सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा संयुक्त रूप से मनोनीत किए गए थे
(b) सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए गए थे
(c) अधिकतर सदस्य प्रान्तीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे
(d) सभी सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित किए गए थे।

उत्तर : (c) **UPPSC APS 2013**

व्याख्या– भारत के संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा के अधिकतर सदस्य प्रान्तीय विधान सभाओं के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किये गये थे।

5. भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को–

(a) ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया
(b) गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया
(c) विभिन्न प्रान्तों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया
(d) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया

उत्तर–(c) **UPPCS (Pre.) G.S., 1993**

व्याख्या– उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

6. भारत की संविधान सभा की अन्तिम बैठक की सही तिथि बताइए।

(a) 26 नवम्बर, 1949 (b) 5 दिसम्बर, 1949
(c) 24 जनवरी, 1950 (d) 25 जनवरी 1950

उत्तर-(c) **U.P.P.C.S. (Pre), 2018**

व्याख्या– संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसम्बर, 1946 को हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा ने की।
इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुए थे। इन अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा की अन्तिम बैठक (12वीं बैठक) 24 जनवरी, 1950 को हुई, इसी दिन सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया तथा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति (अन्तरिम राष्ट्रपति) चुना गया और संविधान सभा भंग कर उसे अन्तरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था।

7. भारत की संविधान सभा का गठन किया गया–

(a) क्रिप्स प्रस्तावों के अन्तर्गत
(b) कैबिनेट मिशन योजना के अन्तर्गत
(c) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अन्तर्गत
(d) माउन्टबेटन योजना के अन्तर्गत

उत्तर–(b) **UPPCS (Mains) Spl. G.S. IInd 2004, 2008**
UPUDA/LDA (Pre.) G.S., 2010
U.P. Lower (Pre.) G.S. 2009
UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 2008, 2002

व्याख्या–भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अन्तर्गत किया गया था। यह मिशन 24 मार्च, 1946 को दिल्ली पहुँचा था तथा अपनी योजना 16 मई, 1946 को प्रस्तुत की। मन्त्रिमण्डलीय मिशन की सिफारिश थी कि संविधान सभा में प्रान्तों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में हो जिसमें सामान्यतः एक प्रतिनिधि का निर्वाचन दस लाख जनसंख्या पर हो।

8. कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद् में प्रत्येक प्रान्त को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था?

(a) 8 लाख व्यक्ति (b) 10 लाख व्यक्ति
(c) 12 लाख व्यक्ति (d) 15 लाख व्यक्ति
उत्तर–(b) **UPUDA/LDA (Pre.) G.S., 2001**

व्याख्या– उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

9. कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अन्तरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे?
(a) 15 सदस्य (b) 25 सदस्य
(c) 16 सदस्य (b) 14 सदस्य
उत्तर–(d) **UPPCS (Pre) Opt. Political Science 2010**

व्याख्या–कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अन्तरिम सरकार में लार्ड माउण्ट बेटन अध्यक्ष थे। जिसमें जवाहर लाल नेहरू उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा 14 अन्य (सदस्य) लोग जिसमें बल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह, जान मथाई, सी. राजगोपालाचारी, सी.एच. भाभा, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, आसफ अली, जगजीवन राम, लियाकत अली खाँ, आई.आई. चुन्दरीगर, अब्दुल रब निश्तार, जोगेन्द्र नाथ मण्डल, गजनफर अली खाँ शामिल थे। प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गयी।

10. कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया–
(a) एकात्मक सरकार
(b) शक्तिशाली केन्द्र सहित संघात्मक सरकार
(c) कमजोर केन्द्र सहित संघात्मक सरकार
(d) संघात्मक सरकार जिसमें ब्रिटिश प्रान्तों को पृथक् होने का अधिकार था।
उत्तर–(c) **UPPCS (Pre) Opt. Political Science 2010**

व्याख्या–कैबिनेट मिशन योजना, 1946 में भारत के लिए कमजोर केन्द्र सहित संघात्मक सरकार के गठन का प्रस्ताव था। इसमें ब्रिटिश भारत और प्रान्तों को मिलाकर संघ की स्थापना का प्रस्ताव था। जिसमें भारतीय रियासतों को सम्मिलित न होने की छूट थी। कुछ राष्ट्रीय हितों के विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों को प्रान्तों के अधिकार क्षेत्र में रखने का प्रस्ताव था।

11. निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था?
(a) जे.बी. कृपलानी (b) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
(c) के. एम. मुंशी (d) टी.टी. कृष्णामाचारी
उत्तर–(b) **(UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 2010)**

व्याख्या– डॉ. बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा में एक गैर कांग्रेसी सदस्य थे। डॉ. अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य के रूप में बम्बई से निर्वाचित हुए थे।

12. निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व, भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था?
(a) लिबरल पार्टी (b) हिन्दू महासभा
(c) शिड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन (d) कम्युनिस्ट पार्टी
उत्तर : (a) **(UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 1998)**

व्याख्या– भारत की संविधान निर्मात्री सभा में लिबरल पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं था। हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से, शिड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के बी.आर. अंबेडकर बम्बई से तथा कम्युनिस्ट पार्टी के सोमनाथ लाहिड़ी बंगाल से संविधान सभा के सदस्य थे।

13. भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन (First day session) की अध्यक्षता इन्होंने की थी –
(a) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (b) पंडित जवाहरलाल नेहरु
(c) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (d) डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा
उत्तर – (d) **UPPCS (Pre.) G.S., 2006**
UPPCS (Mains) G.S. II[nd] Paper 2013
UPPSC GIC 2015

व्याख्या– संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉ0 सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई।

14. संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था –
(a) 16 अगस्त, 1947 को (b) 26 जनवरी, 1948 को
(c) 9 दिसम्बर, 1946 को (d) 26 नवम्बर, 1946 को
उत्तर : (c) **UPPCS (Mains) G.S. II[nd] Paper 2009, 2011**
UPPCS (Pre.) G.S., 1995
UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 1990

व्याख्या – उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

15. संविधान सभा की प्रान्तीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था?
(a) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (b) पंडित जवाहरलाल नेहरू
(c) डॉ राजेन्द्र प्रसाद (d) सरदार पटेल
उत्तर–(d) **UPPCS (Mains) G.S. II[nd] Paper 2008**

व्याख्या – संविधान सभा की प्रान्तीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
संविधान सभा की मुख्य समितियाँ और उनके अध्यक्ष इस प्रकार हैं–
1. नियम समिति - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
2. संचालन समिति - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
3. राज्यों के लिए (समझौता) समिति – जवाहर लाल नेहरू
4. प्रारूप समिति - डॉ. भीमराव अम्बेडकर
5. सलाहकार समिति - सरदार वल्लभभाई पटेल

इस समिति की दो उपसमितियाँ थीं –
क. मूल अधिकार उपसमिति - जे. बी. कृपलानी
ख. अल्पसंख्यक उपसमिति - एच. सी. मुखर्जी
6. संघ शक्ति समिति - जवाहर लाल नेहरू
7. संघ संविधान समिति - जवाहर लाल नेहरू
8. प्रान्तीय संविधान समिति - सरदार वल्लभ भाई पटेल।

16. संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था?
(a) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (b) के. टी. शाह
(c) डॉ. बी. एन. राव (d) ए. के. अय्यर
उत्तर (c) **UPPCS (Pre.) G.S. 2014**
UP Lower (Pre) G.S., 1998

व्याख्या : 11 दिसम्बर,1946 की बैठक में समितियों-उपसमितियों तथा संविधान सभा के अध्यक्ष की सहायता के लिए सर बेनेगल एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। सभा के सांविधानिक सलाहकार सर बी. एन. राव ने अक्टूबर, 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। इसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं। 29 अगस्त, 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का निर्वाचन किया। डॉ. भीमराव अम्बेडकर समिति के सभापति नियुक्त हुए। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या सात थी, जो इस प्रकार है– 1. डॉ. भीमराव अम्बेडकर (अध्यक्ष) 2. एन. गोपाल स्वामी आयंगर 3. अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर 4. कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी 5. सैय्यद मोहम्मद सादुल्ला 6. एन. माधव राव (बी.एल. मित्र के स्थान पर) 7. टी.टी. कृष्णामाचारी (1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात्)

17. भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था

(a) बी. आर. अम्बेडकर द्वारा (b) बी. एन. राव द्वारा
(c) के. सन्थानम द्वारा (d) के. एम. मुन्शी द्वारा

उत्तर–(b) **U.P. Lower (Pre.) G.S. 2009**
U.P. PCS (Pre.) G.S. 2009

व्याख्या– उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

18. संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था?

(a) मोहम्मद सादुल्लाह (b) के.एम. मुंशी
(c) ए.के. अय्यर (d) जवाहर लाल नेहरू

उत्तर – (d) **UPPCS (Mains) G.S. II[nd] Paper 2012**

व्याख्या – उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

19. संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या थी –

(a) सात (b) नौ
(c) ग्यारह (d) तेरह

उत्तर – (a) **UPPCS (Mains) G.S.-II[nd] Paper, 2006**
UP Lower (Pre) G.S., 2008
UPPCS Tax Inspector Exam 1997

व्याख्या – उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

20. निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे?

(i) एन. गोपालास्वामी (ii) जवाहरलाल नेहरू
(iii) अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर (iv) सरदार पटेल

नीचे दिये गये कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए :

कूट :

(a) (i), (iii) और (iv) (b) (i) और (iv)
(c) (i) और (iii) (d) (ii), (iii) और (iv)

उत्तर – (c) **UPPCS (Pre.) G.S., 2014**

व्याख्या – उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

21. संविधान सभा ने डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया?

(a) 13 दिसंबर, 1946 (b) 22 जनवरी, 1947
(c) 3 जून, 1947 (d) 29 अगस्त, 1947

उत्तर – (d) **UPPCS (Mains) G.S. II[nd] Paper 2008**

व्याख्या– उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

22. संविधान निर्मात्री परिषद् की 'झण्डा समिति' के अध्यक्ष कौन थे–

(a) सी. राजगोपालाचारी (b) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
(c) जे.बी. कृपलानी (d) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर

उत्तर–(b) **UPPCS (Pre.) G.S., 1991**

व्याख्या– संविधान निर्मात्री परिषद् की झण्डा समिति के अध्यक्ष डा. राजेन्द्र प्रसाद थे। इस समिति के द्वारा 22 जुलाई, 1947 को पेंगाली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए भारतीय ध्वज को स्वीकार किया गया।

23. भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे-

(a) बी.आर. अम्बेडकर (b) जवाहर लाल नेहरू
(c) सरदार पटेल (d) महात्मा गाँधी

उत्तर – (c) **(UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 1994)**
(UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 1993)

व्याख्या – भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष सरदार बल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा सलाहकार समिति का गठन सरदार बल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया। इसकी एक उपसमिति मौलिक अधिकारों पर थी। इस मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे।

24. भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया–

(a) 26 नवम्बर, 1949 को (b) 15 अगस्त, 1949 को
(c) 2 अक्टूबर, 1949 को (d) 15 नवम्बर, 1949 को

उत्तर-(a) **(UPPCS (Pre) G.S. 2000, 2002, 2006)**
(UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 1990, 93, 94)
U.P. UDA/LDA (Pre.) G.S. 2006
UPPCS (Mains) G.S. II[nd] Paper 2012
UPPCS (Pre.) G.S., 2002
UPPCS (Mains) G.S. II[nd] 2006, 2010, 2013

व्याख्या- भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर, 1949 को अंगीकृत किया गया। सम्पूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे।

25. भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा?

(a) 2 वर्ष 11 माह 18 दिन (b) 2 वर्ष 7 माह 23 दिन
(c) 3 वर्ष 4 माह 14 दिन (d) 3 वर्ष 11 माह 5 दिन

उत्तर - (a) **UPPCS (Mains) G.S. II[nd] Paper 2007**

व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

26. भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था–

(a) जनवरी 22, 1946 (b) जनवरी, 22, 1947

(c) फरवरी 20, 1947 (d) जुलाई 26, 1946

उत्तर–(b) **UPPCS (Pre.) G.S., 1998**

व्याख्या– भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी, 1947 को पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान सभा को इसके मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा दर्शन दिये, जिनके आधार पर इसे संविधान निर्माण कार्य करना था। अंततः 22 जनवरी, 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया।

27. भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है?

''भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है।''

(a) बी. आर. अम्बेडकर (b) एम. वी. पायली

(c) एलेक्जैण्ड्रोविक्स (d) के. सी. व्हीयर

उत्तर : (d) **UPPCS (Mains) G.S. IInd 2005**

व्याख्या : के. सी. ह्वीयर के अनुसार, ''भारतीय संविधान अतिकठोरता तथा अतिलचीलापन के बीच अच्छा संतुलन स्थापित करता है।''

28. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है?

(a) के.एम. मुन्शी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे।

(b) संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया।

(c) बलवन्त राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई।

(d) संविधान के अन्तर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है।

उत्तर – (d) **U.P. Lower (Pre.) G.S. 2013**

व्याख्या– भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 और 32 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) को भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों का संरक्षक घोषित किया गया है।

29. किसने कहा था ''संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था?''

(a) ऑस्टिन

(b) सी.आर. एटली

(c) विन्स्टन चर्चिल

(d) लॉर्ड माउण्टबैटन

उत्तर – (a) **UP RO/ARO (Pre) G.S., 2013**

व्याख्या– प्रसिद्ध ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल आस्टिन ने संविधान सभा में कांग्रेस के प्रभाव को तथा संपूर्ण भारत में कांग्रेस की लोकप्रियता को स्वीकार करते हुए कहा कि ''संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। 'दि इंडियन कॉस्टीट्यूशन' इनकी प्रमुख रचना है।

30. इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था?

(a) जवाहरलाल नेहरू

(b) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर

(c) मौलाना अबुल कलाम आजाद

(d) टी.टी. कृष्णमाचारी

उत्तर – (b) **UPPCS (Mains) G.S. Ist Paper 2012**

व्याख्या– अन्तरिम सरकार में योगेन्द्र नाथ मण्डल विधि मंत्री थे जबकि स्वतन्त्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉ. भीमराव अम्बेडकर थे।

31. कथन (A) : भारत का एक लिखित संविधान है।

कारण (R) : भारत में एक संविधान-सभा थी।

संकेत :

(a) A तथा R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है

(b) A तथा R दोनों सही हैं, किन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है

(c) A सही है, किन्तु R गलत है

(d) A गलत है, किन्तु R सही है

उत्तर : (a) **(UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 1995)**

व्याख्या : भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। इसका निर्माण एक संविधान सभा ने एक निश्चित तिथि को किया था। अतः A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।

32. भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं?

(a) 15 (b) 13

(c) 12 (d) 10

उत्तर : (a) **U.P. PSC Kanoongo Exam. 2015**

व्याख्या-भारतीय संविधान सभा (Indian Constituent Assembly) में कुल 15 महिला सदस्य थीं। जिनमें (1) विजय लक्ष्मी पंडित (2) राजकुमारी अमृता कौर (3) सरोजनी नायडू (4) सुचेता कृपलानी (5) पूर्णिमा बनर्जी (6) लीला राय (7) जी. दुर्गाबाई (8) हंसा मेहता (9) कमला चौधरी (10) रेणुका राय (11) मालती चौधरी (12) दक्षयानी वेलायुदन (13) बेगम एजाज रसूल (14) ऐनी मस्करीनी (15) अम्मु स्वामीनाथन।

33. संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारम्भ हुआ था?

(a) 14 नवम्बर, 1949

(b) 14 नवम्बर, 1948

(c) 25 नवम्बर, 1948

(d) 25 नवम्बर, 1949

उत्तर : (a) **U.P. PSC Kanoongo Exam. 2105**

व्याख्या- संविधान पर तीसरी बार 14 नवम्बर, 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने 'द कॉन्स्टीट्यूशन ऐज़ सैटल्ड बाई द असेंबली बी पास्ड' प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप को पेश कर इस प्रस्ताव को 26 नवंबर, 1949 को पारित कर दिया गया।

3. संविधान पर विदेशी प्रभाव
(Foreign Effects on Constitution)

1. 'क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो ..... अंग्रेज जा चुके हैं, परन्तु वे शरारत छोड़ गये हैं।'
निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था?
(a) सोमनाथ लाहिड़ी (b) जवाहरलाल नेहरू
(c) सरदार वल्लभ भाई पटेल (d) एन. जी. रंगा
उत्तर–(c) **UPPSC (Pre) 2021**

व्याख्या–संविधान सभा के बहस में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि 'क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हों अंग्रेज जा चुके हैं परन्तु वे शरारत छोड़ गए हैं।'

2. भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है?
(a) यूनाइटेड किंगडम (यू. के.) - ब्रिटेन
(b) यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (यू. एस. ए.)
(c) आयरलैण्ड
(d) जापान
उत्तर : **(c)** **UPPCS (Mains) G.S. II[nd] Paper 2005**
UPUDA/LDA (Pre.) G.S., 2006, 2010
UP RO/ARO (Pre) G.S., 2014
UPPCS (Mains) G.S.-II[nd] 2006
UPPCS (Mains) G.S. II[nd] 2017
UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 2006, 2004

व्याख्या– भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैण्ड के संविधान से लिए गए हैं। भारत का संविधान का विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है।
भारतीय संविधान के स्रोत
ब्रिटिश संविधान-संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया और इकहरी नागरिकता, विधि का शासन।
संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान-मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति।
फ्रांस-गणतंत्रात्मक ढाचा, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श
आयरलैण्ड का संविधान-राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान आदि से संबंधित विशिष्ट व्यक्तियों के मनोनयन की प्रणाली।
ऑस्ट्रेलिया का संविधान- प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, वाणिज्य समागम संयुक्त बैठक।
कनाडा का संविधान- संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां, सबल केन्द्रीय प्रणाली।
जर्मनी का वाइमर संविधान-आपातकाल में राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार सम्बन्धित शक्ति।
दक्षिण अफ्रीका का संविधान-संविधान संशोधन की पद्धति।
जापान का संविधान- विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
पूर्व सोवियत संघ का संविधान-मूल-कर्तव्य।

3. निम्नलिखित में से कौन-सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है?
(प्रावधान) **(स्रोत)**
(a) मौलिक अधिकार - संयुक्त राज्य अमेरिका
(b) राज्य के नीति निर्देशक तत्व - आयरलैण्ड
(c) केन्द्र की अवशिष्ट शक्तियाँ - ऑस्ट्रेलिया
(d) आपातकालीन शक्तियाँ - जर्मनी
उत्तर–(c) **UPPSC (Pre) 2021**

व्याख्या– उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

4. भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है।
(a) यू.एस.ए (b) ब्रिटेन
(c) फ्रांस (d) रसिया (रूस)
उत्तर–(a) **UPPSC AE- 2007 (I)**
UPPCS Rajkeeya Pravakta Pariksha 2017

व्याख्या– उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

5. निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है?
(a) सम्प्रभुता (b) लोकतंत्रात्मक
(c) पंथनिरपेक्ष (d) संघीय
उत्तर–(d) **UPPSC (Pre) 2021**

व्याख्या–भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्प्रभुता, पंथनिरपेक्षता, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का उल्लेख है। जबकि संघीय शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है।

6. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे किये हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए–

सूची-I (उपबन्ध)	**सूची-II (उद्गम-स्रोत)**
A.समवर्ती सूची	1. जापान का संविधान
B. विधि का शासन	2. आयरलैण्ड का संविधान
C. नीति-निर्देशक तत्व	3. ब्रिटिश संविधान
D. विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया	4. ऑस्ट्रेलिया का संविधान

कूट :
(a) A-1, B-2, C-3, D-4 (b) A-2, B-4, C-3, D-1
(c) A-1, B-3, C-4, D-2 (d) A-4, B-3, C-2, D-1
उत्तर–(d) **UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 2000**

व्याख्या–उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

7. भारत के संविधान में 'समवर्ती सूची' की अवधारणा गृहीत की गई है
(a) ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से (b) यू.एस.ए. के संविधान से
(c) कनाडा के संविधान से (d) ऑस्ट्रेलिया के संविधान से
उत्तर-(d) **UPPCS (Mains) G.S. II[nd] 2011, 12, 14, 16**
UPPSC Asstt. Forest Conservator Exam. 2015
UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 1990, 1993, 2006
UPPCS (Pre.) G.S., 1994, 1988, 1999, 2000
U.P. Lower (Pre.) Spl. G.S. 2004
UPPCS (Main) Spl. G.S. II[nd] Paper 2008

व्याख्या- उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

8. राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुये थे।

(a) आयरिश गणतन्त्र (b) कनाडा
(c) संयुक्त राज्य अमेरिका (d) ऑस्ट्रेलिया

उत्तर–(a) **UPPCS (Pre.) G.S., 1998**
UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 2000

व्याख्या–उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

9. हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं -

(a) केवल भारत में
(b) केवल यू. के. में
(c) केवल यू. एस. ए. में
(d) भारत और यू.एस.ए. दोनों में

उत्तर–(d) **UPPCS (Pre.) G.S., 1998, 2008**
UPPCS (Mains) G.S. II[nd] 2006, 2012, 2013

व्याख्या–न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत और यू.एस.ए. दोनों देशों में है। न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत न्यायालयों को शक्ति है कि वह विधानमंडल के कानूनों तथा कार्यपालिका के आदेशों की जाँच कर सकते हैं और यदि ये कानून अथवा आदेश संविधान के विरुद्ध हो तो उनको असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर सकते हैं। भारतीय संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को अनु. 13, 32, 226 में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है।

10. भारतीय संविधान में मौलिक कर्त्तव्यों का विचार लिया गया है –

(a) अमेरिकन संविधान से (b) ब्रिटिश संविधान से
(c) रूस के संविधान से (d) फ्रांस के संविधान से

उत्तर-(c) **UP Lower (Pre) G.S., 2003-04**

व्याख्या– सोवियत संघ (रूस) के संविधान से प्रेरणा ग्रहण करके स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग 4(क) को जोड़ा गया। इसमें मात्र एक अनुच्देद 51क में नागरिकों के लिए दस मूल कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया। वर्तमान में अनु0 51क के अन्तर्गत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य अनु. 51क (ट) 86वां संविधान संशोधन (2002) के द्वारा जोड़ा गया।

11. भारत के संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्त्तव्यों को ग्रहण किया गया है–

(a) संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से
(b) विघटित सोवियत संघ के संविधान से
(c) कनाडा के संविधान से
(d) स्विट्जरलैण्ड के संविधान से

उत्तर–(b) **UPPCS (Pre) Opt. Spl. Pol. Science 2004**
UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 2000

व्याख्या—उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

12. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश 'कानून के समक्ष समानता' किस संविधान से उद्धृत है?

(a) ब्रिटेन (b) संयुक्त राज्य अमेरिका
(c) फ्रांस (d) कनाडा

उत्तर–(a) **UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 2000, 2009**

व्याख्या – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश 'कानून के समक्ष समानता' ब्रिटेन के संविधान से उद्धृत है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के राज्यक्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। 'कानून का समान संरक्षण' शब्दावली अमेरिका के संविधान से लिया गया हैं।

13. नीचे दो सूचियाँ दी गयी हैं। एक में भारतीय संविधान के प्रावधान हैं तथा दूसरे में वे देश जहाँ से उन्हें ग्रहण किया गया है। उन्हें सुमेलित कीजिये तथा सूचियों के नीचे दिये गये कूट का प्रयोग करते हुये सही उत्तर का चयन कीजिये–

सूची-I	**सूची-II**
A. विधि के समक्ष समानता	1. संयुक्त राज्य अमेरिका
B. विधि का समान संरक्षण	2. इंग्लैण्ड
C. विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया	3. जापान
D. शैक्षणिक संस्थाओं के लिये राज्य द्वारा अनुदान	4. आयरलैण्ड

कूट :

	A	**B**	**C**	**D**		**A**	**B**	**C**	**D**
(a)	1	2	4	3	(b)	2	1	3	4
(c)	2	4	1	3	(d)	1	2	3	4

उत्तर–(b) **UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 2004**

व्याख्या–भारतीय संविधान में विश्व के संविधानों से प्रेरणा ली गई है विधि के समक्ष समता- ग्रेट ब्रिटेन, विधि का समान संरक्षण - अमेरिका, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया-जापान, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान - आयरलैण्ड।

14. भारतीय संविधान के सोतों की दृष्टि में निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप में संबद्ध नहीं है :

(a) कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द लिया गया है
(b) अमेरिकी संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है
(c) ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई है
(d) आस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है

उत्तर : (d) **(UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 1996)**

व्याख्या : आस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई तथा संविधान संशोधन प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है।

15. भारत में संघ-राज्य संबंध में ..... समानता पायी जाती है।

1. आस्ट्रेलियाई संविधान
2. कनाडाई संविधान
3. भारत सरकार अधिनियम 1935
4. अमेरिका संविधान

निम्नलिखित कोड से सही उत्तर का चयन करें।

(a) 1और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 3 और 4

उत्तर–(b) **UPPSC AE- 2007 (I)**

व्याख्या– भारत में संघ राज्य संबंध कनाडा के संविधान एवं भारत सरकार अधिनियम, 1935 के नियमों से साम्य रखते है। भारतीय संघवाद कनाडा देश की पद्धति से प्रभावित है।

4. संविधान की प्रस्तावना/उद्देशिका-विषयवस्तु एवं महत्त्व
(Preamble of the Constitution - Subject & its Importance)

1. निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन-सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है?

(a) विचार की स्वतन्त्रता (b) आर्थिक स्वतन्त्रता
(c) अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता (d) विश्वास की स्वतन्त्रता

UPPSC ACF/RFO 2021 Paper-II

Ans. (b) : भारत के संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतन्त्रता वर्णित नहीं है। जबकि पाँच प्रकार की स्वतन्त्रता का उल्लेख है जैसे- विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, एवं उपासना। तीन प्रकार के न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा दो प्रकार की समानता जैसे- प्रतिष्ठा और अवसर का उल्लेख मिलता है।

2. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है?

(a) सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक
(b) सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक
(c) सामाजिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक
(d) सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक

उत्तर-(d) **UPPSC RO/ARO (Pre) 2021**

व्याख्या—उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

3. भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के 'न्याय' की व्यवस्था की गयी है?

(a) 02 (b) 03 (c) 04 (d) 05

उत्तर–(b) **UPPSC ADO 2014**

व्याख्या—उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

4. निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया?

(a) केशवानंद भारती केस (b) बेरुबारी केस
(c) सज्जन सिंह केस (d) गोलकनाथ केस

UPPSC ACF/RFO 2021 Paper-II

Ans. (b) : बेरुबारी केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया। इसलिये यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। किन्तु केशवानन्द भारती वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा माना है।

5. किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है?

(a) बेरुबारी (b) सज्जन सिंह
(c) गोलकनाथ (d) केशवानन्द भारती

उत्तर–(a) **UPPCS (Mains) 2017 G.S. IInd Paper**

व्याख्या– उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

6. संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है?

(a) यह लागू किया जा सकता है
(b) यह लागू नहीं किया जा सकता है
(c) विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर–(b) **UPPCS Pre-2019**

व्याख्या– संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि वह लागू नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूबारी वाद (1960) में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। परंतु केशवानन्द भारती वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना था। अतः स्पष्ट है प्रस्तावना या उसके किसी भाग को विधिक रूप से न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है।

7. कथन (A) : भारत का संविधान सबसे अधिक लम्बा हो गया है।
कारण (R) : मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है।
नीचे दिये गये कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए :
कूट :
(a) (A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
(b) (A) तथा (R) दोनों सही हैं, परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(c) (A) सही है, परन्तु (R) गलत है।
(d) (A) गलत है, परन्तु (R) सही है।

उत्तर–(b) **UPPCS (Pre) G.S., 2015**

व्याख्या—उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

8. निम्नलिखित में से किस एक का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है?

(a) संप्रभु (b) समाजवादी
(c) गणतंत्र (d) संघात्मक

उत्तर (d) **UPPSC Food Safety Inspector Exam, 2013**
UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 1994
U.P. PCS Asst. State Officer-2014

व्याख्या- उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

9. किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द 'समाजवादी' एवं 'पथ निरपेक्ष' जोड़े गये?

(a) 1976 (b) 1977 (c) 1978 (d) 1979

उत्तर–(a) **UPPSC (G.I.C 2009)**
UPPSC Asstt. Forest Conservator Exam, 2015

व्याख्या– 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' पंथनिरपेक्षता और अखण्डता शब्द जोड़े गए। संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है।

10. भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है:

(a) धर्म निरपेक्ष (b) समाजवादी, धर्म निरपेक्ष
(c) समाजवादी (d) गणतंत्रात्मक

उत्तर- (b) **(UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 1990)**

व्याख्या- उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

11. ये दो शब्द 'धर्मनिरपेक्ष' एवं 'समाजवादी' प्रस्तावना में जोड़े गये। ये कौन सा संविधान संशोधन था?

(a) 25वाँ संशोधन (b) चौथा संशोधन
(c) 42वाँ संशोधन (d) 44वां संशोधन

उत्तर–(c) **UPPCS (Mains) G.S. II[nd] 2017**

व्याख्या– उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

12. 26 नवम्बर, 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे?

1. समाजवादी 2. अखण्डता
3. पंथनिरपेक्ष 4. गणराज्य

अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिये :

कूट :

(a) 1, 2 और 3 (b) 2, 3 और 4
(c) 1, 2 और 4 (d) 3 और 4

उत्तर – (a) **UPPCS (Pre.) G.S., 2009**
UPPCS (Mains) G.S.-II[nd] Paper, 2006, 2013

व्याख्या – उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

13. भारत के संविधान में संबन्धित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

(1) सम्पूर्ण शक्ति का मूलभूत स्रोत जनता है।
(2) भारतीय संघ राज्यों की कृति है।
(3) लोग संविधान के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का उपभोग कर सकते हैं।
(4) संविधान सब लोगों को प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता के लिए आश्वस्त करता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 1, 3 और 4 (d) केवल 2, 3 और 4

उत्तर–(c) **UPPSC APS 2013**

व्याख्या– भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ''हम भारत के लोग'' शब्द का उल्लेख मिलता है जिससे स्पष्ट है कि भारत की सम्पूर्ण शक्ति का स्रोत जनता है। भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का उल्लेख है जिससे स्पष्ट है कि भारतीय संघ राज्यों की कृति नहीं है बल्कि राज्य संघ की कृति हैं। ''भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नही है।'' इसलिए भारतीय संघ के सन्दर्भ में कहा जाता है यह विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है।

प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय शब्द का स्पष्ट उल्लेख है। साथ की सभी भारतीयों को प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता की बात का भी उल्लेख मिलता है।

14. भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है?

(a) 3, 5, 2, 1 (b) 1, 3, 5, 2
(c) 2, 5, 3, 1 (d) 5, 2, 1, 3

उत्तर–(a) **U.P.P.C.S. (Pre), 2018**

व्याख्या–
भारतीय संविधान की उद्देशिका से स्पष्ट है कि–
तीन न्याय– सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय
पाँच स्वतंत्रता– विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता
दो समानता– प्रतिष्ठा और अवसर
भ्रातृत्व– बन्धुत्व

15. भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है?

(a) दो (b) तीन
(c) एक (d) चार

उत्तर-(b) **UPPCS (Mains) G.S. II[nd] Paper, 2016**

व्याख्या—उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

16. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है।

(a) पद तथा अवसर की समानता को
(b) आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को
(c) राजनीतिक तथा सामाजिक न्याय को
(d) सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को

उत्तर- (d) **(UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 2006)**
(UPPCS (Pre) Opt. Spl. Pol. Science 2004)

व्याख्या—उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

17. निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है?

(a) सामाजिक न्याय (b) राजनीतिक न्याय
(c) आर्थिक न्याय (d) धार्मिक न्याय

उत्तर (d) **U.P.P.C.S.(J) G.K., 2016**
UP Lower (Mains) G.S., 2013

व्याख्या- उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

18. भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिये सुनिश्चित करना है-

1. सामाजिक तथा आर्थिक न्याय
2. विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
3. अवसर की समानता
4. व्यक्ति की प्रतिष्ठा

नीचे दी गई कूट-स्कीम में से सही उत्तर का चयन कीजिये-

(a) 1 और 2 (b) 1, 2 और 3
(c) 2, 3 और 4 (d) सभी चारों

उत्तर– (d) **UP Lower (Pre) G.S., 1998**

व्याख्या—उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

19. संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा <u>नहीं</u> करती है?

(a) सामाजिक न्याय (b) राजनीतिक न्याय
(c) विचार की स्वतंत्रता (d) पूजा की समानता

उत्तर–(d) **UPPCS BEO GS 2006**

व्याख्या—उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

20. भारत के संविधान की प्रस्तावना में समानता का प्रावधान है–

1. वेतन का
2. प्रतिष्ठा का
3. अवसर का

नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिये–

कूट -

(a) 1 तथा 2 (b) 1 तथा 3

(c) 2 तथा 3 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर–(c) UP PSC ACF/RFO (Mains) 2019 Paper II

व्याख्या—उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

21. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है?

(a) सात (b) तीन

(c) पाँच (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर–(c) UP PSC ACF/RFO (Mains) 2019 Paper II

व्याख्या—उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

22. निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है?

(a) सामाजवाद

(b) व्यक्ति की गरिमा

(c) योजनाबद्ध विकास

(d) राष्ट्र की एकता और अखण्डता

उत्तर–(c) UPPSC AE-2011

व्याख्या संविधान की प्रस्तावना में योजनाबद्ध विकास की बात नहीं की गई है।

23. भारत की सम्प्रभुता के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. भारत राष्ट्रमण्डल का सदस्य है।
2. राष्ट्रमण्डल की सदस्यता के कारण भारत की सम्प्रभुता कम हो जाती है।

नीचे दिये हुये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये -

कूट :

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 तथा 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर– (a) UPPCS (Mains) 2017 G.S. IInd Paper

व्याख्या– संप्रभु शब्द का आशय है कि, भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं हैं और यह अपने आन्तरिक अथवा बाह्य मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। यद्यपि वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना। राष्ट्रमण्डल की सदस्यता स्वैच्छिक है बाध्यकारी नहीं। तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती। वर्तमान में राष्ट्रमण्डल में 56 देश सम्मिलित हैं।

24. भारतीय संविधान के निर्माण से सम्बन्धित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है?''

1. पं. नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का, जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था।
2. उद्देशिका बहुत महत्त्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है।
3. संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है।
4. राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं।

नीचे दिये गये कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

कूट :

(a) 1,2 और 3 (b) 1, 3 और 4

(c) 2, 3 और 4 (d) सभी चारों

उत्तर–(a) UPPCS (Mains) G.S. IInd Paper 2010

व्याख्या– पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है एवं यह भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। उद्देशिका का प्रारंभ ''हम भारत के लोग'' से होता है जिससे यह सूचित होता है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। ''हम भारत के लोग'' से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है और भारतीय जनता ने अपनी संप्रभु इच्छा को इस संविधान के माध्यम से व्यक्त किया है। भारत में संसदीय प्रजातंत्र (संसदीय व्यवस्था) को अपनाया गया है, जिसमें कार्यपालक प्रधान या राज्य का प्रधान नाम मात्र का प्रमुख होता है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री समेत मंत्रिमण्डल में निहित होती है जो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं।

25. भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिम्बित होता है?

(a) उद्देशिका (b) मूल अधिकार

(c) राज्य की नीति के निदेशक तत्व (d) मूल कर्त्तव्य

उत्तर–(a) UPSC IAS (Pre) 2017

व्याख्या– उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

26. निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिम्बित करता है?

(a) मौलिक अधिकार

(b) संविधान की प्रस्तावना

(c) राज्य के नीति निदेशक तत्त्व

(d) संसद

उत्तर–(b) U.P. Lower (Pre.) G.S. 2013

व्याख्या – उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

27. 26 जनवरी, 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी?

(a) लोकतंत्रात्मक गणराज्य

(b) संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य

(c) संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य

(d) संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य

उत्तर- (b) **UPPCS (Pre) Opt. Pol. Sci. 2007**
UPPCS (Mains) G.S. IInd Paper 2009
U.P. Lower (Pre) G.S. SPl. 2008

व्याख्या- 42वें संविधान संशोधन, 1976 के पूर्व भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्दों का उल्लेख है जो कि 26 जनवरी, 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति को दर्शाता है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन (1976) में जोड़े गए।

28. भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है, वह है-

(a) सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य

(b) सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, गणराज्य, समाजवादी, धर्म-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक

(c) पंथनिरपेक्ष, सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी, गणराज्य

(d) सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (a) **UPPSC ACF (Pre) 2017**

(UPPCS (Pre) Opt. Spl. Pol. Science 2008)

व्याख्या- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्दावली का प्रयोग इसी क्रम में हुआ है।

29. संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एकः

(a) संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य है।

(b) संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है।

(c) समाजवादी, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है।

(d) संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य है।

उत्तर–(b) **UPPCS Tax Inspector-2003**

व्याख्या– उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

30. भारतीय संविधान के किस भाग/भागों में, आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है–

(a) प्रस्तावना और मौलिक अधिकार

(b) प्रस्तावना और नीति-निदेशक सिद्धान्त

(c) मौलिक अधिकार और नीति-निदेशक सिद्धान्त

(d) प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति-निदेशक सिद्धान्त

उत्तर–(b) **UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 2002**

व्याख्या–भारतीय संविधान के प्रस्तावना और नीति निदेशक सिद्धान्त में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है।

31. निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि 'उद्देशिका संविधान का भाग है'?

(a) यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम डॉ. कोहली

(b) बनारसीदास बनाम स्टेट ऑफ यू.पी.

(c) बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

(d) मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब

उत्तर–(c) **UPPCS (Pre) G.S., 2012**

व्याख्या– उच्चतम न्यायालय ने इन री बेरुवारी यूनियन (1960) वाद में मत व्यक्त किया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के मामले में भी उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया है।

32. सर्वोच्च न्यायालय के कौन से निर्णय में तय हुआ कि प्रस्तावना संविधान का अंग है?

(a) गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब

(b) केशवानन्द भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल

(c) ए.के. गोपालन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास

(d) मिनर्वा मिल्स बनाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया

उत्तर–(b) **U.P. PSC Kanoongo Exam. 2015**

U.P.P.C.S.- 1993

व्याख्या–उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

33. भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है–

(a) इटली के संविधान से (b) कनाडा के संविधान से

(c) फ्रांस के संविधान से (d) यू. एस. ए. के संविधान से

उत्तर–(d) **UPPCS (Pre) GS, 2015**

व्याख्या–भारतीय संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना का स्रोत अमेरिकी संविधान है। प्रस्तावना/उद्देशिका संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। आस्ट्रेलिया से उद्देशिका की भाषा को लिया गया है।

34. भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की 'आत्मा' कहलाता है?

(a) मूल अधिकार

(b) राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्व

(c) उद्देशिका

(d) सांविधानिक उपचारों का अधिकार

उत्तर–(c) **UPPCS (Pre) G.S. 2008**

UPPCS (Mains) G.S. IInd Paper 2013, 2015

UP UDA/LDA (Pre) G.S. 2006

व्याख्या – भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के. एम. मुंशी ने इसे 'राजनीतिक जन्मपत्री' कहा है। डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर ने सांविधानिक उपचारों का अधिकार (अनु. 32) को संविधान की आत्मा कहा है।

35. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है।
2. भारत एक प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य है।
3. भारत में लोकतांत्रिक समाज है।
4. भारत एक कल्याणकारी राज्य है।

उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

(a) 1 और 2 केवल (b) 1, 2 और 3 केवल

(c) 2, 3 और 4 केवल (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर – (d) **UPPCS (Mains) G.S. IInd Paper 2012**

व्याख्या – उपर्युक्त प्रश्न के चारों कथन सत्य हैं क्योंकि भारत में जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सरकार का गठन करती है।

संप्रभुता संपन्न राज्य होने के साथ-साथ भारत की सामाजिक व्यवस्था लोकतांत्रिक ढंग से चलती है क्योंकि नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना के साथ अनेक अधिकार प्राप्त है। उद्देशिका और नीति निदेशक तत्त्वों से स्पष्ट होता है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है।

36. निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्म निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है?

(a) मौलिक अधिकार (b) संविधान की प्रस्तावना
(c) 9वीं अनुसूची (d) राज्य के नीति निर्देशक तत्व

उत्तर : (b) **UPPCS (Mains) G.S. II[nd] Paper 2005**

व्याख्या : संविधान की प्रस्तावना भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है।

37. भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द का सही भाव व्यक्त करता है?

(a) भारत में अनेक धर्म है
(b) भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है।
(c) धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है।
(d) भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है।

उत्तर : (d) **UPPCS (Mains) G.S. II[nd] Paper 2005**

व्याख्या : भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अभिप्राय यह नहीं है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं का ख्याल ही नहीं किया जायेगा। इसका अर्थ सिर्फ यह होगा कि संसद को जनता पर किसी विशेष धर्म को थोपने की शक्ति नहीं होगी। अर्थात राज्य धर्म के प्रति तटस्थता का भाव रखेगा।

38. निम्न में से किसे 'पंथ निरपेक्ष राज्य' कहा जाएगा?

(a) जो राज्य धर्म-विरोधी हो
(b) जो राज्य अधार्मिक हो
(c) वह राज्य जिसका कोई धर्म न हो तथा जो धर्म के आधार पर भेदभाव न करता हो
(d) वह राज्य जो सभी धर्मों को राज्य का धर्म घोषित करता हो

उत्तर–(c) **UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 2008**

व्याख्या – उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

39. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गयी है उनकी आगे व्याख्या की गयी है-

(a) मूल अधिकारों के अध्याय में
(b) राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों के अध्याय में
(c) मूल अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों एवं मौलिक कर्त्तव्यों के अध्यायों में
(d) संविधान के पाठ में कहीं नहीं

उत्तर-(c) **UP Lower (Pre) Spl. G.S., 2002**

व्याख्या– भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गयी है उनकी आगे मूल अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों एवं मौलिक कर्त्तव्यों के अध्यायों में व्याख्या की गई है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए नीति निदेशक तत्वों में उल्लेख है जबकि विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता का वर्णन मूल अधिकारों में किया गया है। मूल कर्तव्यों के भाग में नागरिकों के लिए सार्वजनिक संपत्ति और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान जैसी बातें राष्ट्र की एकता और अखण्डता को बढ़ावा देने से संबद्ध हैं।

40. निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है?

(a) कल्याणकारी राज्य (b) समाजवादी राज्य
(c) राजनीतिक समानता (d) साम्यवादी राज्य

उत्तर–(d) **UP Lower (M) G.S. 2015-16**

व्याख्या– साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निदेशक तत्व से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्पष्ट होती है जबकि समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है।

41. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ''संविधान के आधारभूत ढाँचे'' के सिद्धांत को स्पष्ट किया–

(a) गोलकनाथ वाद 1967 में
(b) केशवानन्द भारती वाद 1973 में
(c) शंकरी प्रसाद वाद 1951 में
(d) सज्जन सिंह वाद 1965 में

उत्तर–(b) **UP PSC (Pre) 2020**

व्याख्या– संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान और भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। इन प्रावधानों को संविधान संशोधन के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है। भारत में संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत केशवानन्द भारती वाद 1973 द्वारा स्पष्ट किया गया था।

42. निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के 'मूलभूत ढाँचे' की अवधारणा प्रतिपादित की गई है?

(a) इन्दिरा साहनी वाद (b) शंकरी प्रसाद का वाद
(c) रुदल शाह का वाद (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर–(d) **UP Lower (M) G.S. 2013**

व्याख्या—उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

43. निम्नलिखित में से कौन-सी शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है?

(a) वार्षिक वित्तीय विवरण (b) विनियोग विधेयक
(c) बजट (d) भारत की संचित निधि

उत्तर–(c) UP PSC ACF/RFO (Mains) 2018 Paper II

व्याख्या– भारतीय संविधान में बजट शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। यह फ्रेंच भाषा के शब्द बुजेट से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। इसी में वित्तीय वर्ष के आय एवं व्यय से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण बजट कहा जाने लगा। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में Annual Financial Statement यानी वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। जिसे आम बोलचाल की भाषा में बजट कहा जाता है।

5. संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची एवं विभिन्न भाग (Articles, Schedule & Parts of the Constitution)

1. निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिये तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है, व्यवस्थित कीजिये।

I. संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र
II. मौलिक कर्त्तव्य
III. नागरिकता
IV. राज्य की नीति के निदेशक तत्व

नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर का चयन कीजिये

कूटः

(a) IV, II, III, I (b) I, III, IV, II
(c) III, I, II, IV (d) II, IV, I, III

उत्तर-(b) **UPPSC (Pre) 2022**

व्याख्या- भारतीय संविधान को 22 भागों और 395 अनुच्छेदों में बाँटा गया है। संविधान के भागों का सही सुमेलन निम्नलिखित है-

(संविधान के भाग)	(विषय)
भाग-1	संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र
भाग-2	नागरिकता
भाग-3	मौलिक अधिकार
भाग-4	राज्य की नीति के निदेशक तत्व
भाग-4A	मौलिक कर्तव्य

2. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिये तथा सूचियों के नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर का चयन कीजिये।

सूची-I (अनुसूची)		सूची-II (विषय)	
A.	तृतीय अनुसूची	1.	राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन
B.	चतुर्थ अनुसूची	2.	शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप
C.	सातवीं अनुसूची	3.	भाषाएँ
D.	आठवीं अनुसूची	4.	संसद और राज्य विधान मण्डलों द्वारा बनायी जाने वाली विधियों की विषय सूची

कूटः

	A	B	C	D
(a)	1	2	3	4
(b)	3	4	2	1
(c)	2	1	4	3
(d)	4	3	1	2

उत्तर-(c) : **UPPSC (Pre) 2022**

व्याख्या- निम्नलिखित सूचियाँ सही सुमेलित हैं-

अनुसूची		विषय
तृतीय अनुसूची	-	शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप
चतुर्थ अनुसूची	-	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य सभा में स्थान का आवंटन
सातवीं अनुसूची	-	संसद और राज्य विधान मण्डलों द्वारा बनायी जाने वाली विधियों की विषय सूची
आठवीं अनुसूची	-	भाषाएँ

3. भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है?

(a) अनुच्छेद 341 (b) अनुच्छेद 342
(c) अनुच्छेद 343 (d) अनुच्छेद 344

उत्तर-(c) **UPPSC Staff Nurse 2022**

व्याख्या- अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। संविधान के भाग XVII में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के सम्बंध में व्यवस्था की गई है।

4. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 कुछ भारतीय राज्यों के लिये विशेष प्रावधान करता है। नीचे दिये हुये राज्यों में कौन इस अनुच्छेद के अन्तर्गत नहीं आता है?

(a) महाराष्ट्र (b) गुजरात
(c) केरल (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर-(c) **UPPSC ACF/RFO 2021 Paper-II**

व्याख्या- भारतीय संविधान के भाग-21 में अनुच्छेद 371 से 371- 'ञ' तक बारह राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान किये गये हैं। इन राज्यों के नाम हैं- महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक एवं गोवा। जबकि केरल को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान का उद्देश्य इन राज्यों के पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना, जनजातीय लोगों के आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना है।

5. भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल-बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है?

(a) 9 वीं (b) 12वीं
(c) 11वीं (d) 10वीं

उत्तर-(d) **UPPSC AE 2021**

व्याख्या- भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल-बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है। इसे वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया।

6. निम्न में से कौन-सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि 'उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिये बाध्यकारी होगा'?

(a) अनुच्छेद 140 (b) अनुच्छेद 143
(c) अनुच्छेद 142 (d) अनुच्छेद 141

उत्तर-(d) **UPPSC AE 2021**

व्याख्या- अनुच्छेद 141 के अनुसार ''उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिये बाध्यकारी होगा।''

7. 1993 में, निम्नलिखित में से कौनसी भाषा आठवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गयी?

(a) मैथिली (b) संथाली
(c) बोडो (d) डोगरी

उत्तर-(*) **UPPSC RO/ARO (Pre) 2021**

व्याख्या- 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में मैथिली, डोगरी, बोडो एवं संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। आठवीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषायें सम्मिलित हैं।

नोट- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर (b) माना है।

8. आठवीं अनुसूची में संविधान (92वाँ संशोधन) अधिनियम द्वारा कौन-सी भाषा नहीं जोड़ी गई?

(a) बोडो (b) कोंकणी
(c) डोगरी (d) संथाली

उत्तर-(b) **UP PSC COMPUTER ASSISTANT 2019**

व्याख्या– उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

9. भारत के संविधान के भाग IX-A में, निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाईयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया-

1. ग्रामीण क्षेत्र
2. शहरी क्षेत्र

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए :

कूट-

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और ना ही 2

उत्तर-(b) **UPPSC RO/ARO (Mains) 2021**

व्याख्या- भारतीय संविधान के भाग IX-A में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन इकाईयों को 1992 के 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसे 'नगरपालिकाएं' नाम दिया गया।

10. संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है-

(a) 100 (b) 108
(c) 110 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर-(b) **UPPSC RO/ARO (Mains) 2021**

व्याख्या- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अधीन किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध की अवस्था में संयुक्त, अधिवेशन का उपबंध किया गया है।

11. भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार, भारत की सरकार का कानूनी नाम है-

(a) द यूनियन गवर्नमेंट (b) द यूनियन ऑफ इण्डिया
(c) इण्डिया (d) भारत

उत्तर-(b) **UPPSC RO/ARO (Mains) 2021**

व्याख्या- भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम- 'द यूनियन ऑफ इण्डिया' है। भारत सरकार, भारत संघ के नाम से 'वाद' ला सकेगी या उस पर 'वाद' लाया जा सकेगा।

12. निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है?

(a) 200 (b) 250
(c) 280 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर-(c) **UPPSC RO/ARO (Mains) 2021**

व्याख्या- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर पाँचवें वर्ष या आवश्यकतानुसार उससे पहले भी किया जाता है।

13. भारतीय संविधान के छठीं अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू होते हैं?

(a) गुजरात (b) छत्तीसगढ़
(c) त्रिपुरा (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर-(c) **UPPSC ACF/RFO 2021 Paper-II**

व्याख्या- भारतीय संविधान के छठीं अनुसूची के प्रावधान त्रिपुरा, असम, मेघालय व मिजोरम में जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए स्वायत्त स्थानीय प्रशासन का अधिकार प्रदान करती है। यह विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत प्रदान किया गया है।

14. भारतीय संविधान की छठीं अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं?

(a) त्रिपुरा (b) सिक्किम
(c) नागालैण्ड (d) उपरोक्त सभी

उत्तर–(a) **UPPCS Pre-2019**

व्याख्या–उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

15. निम्नलिखित मे से कौन सही सुमेलित नहीं है?

	प्रावधान	**अनुच्छेद**
(a)	सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति	- 127
(b)	लोकसभा के अध्यक्ष	- 93
(c)	संसद के सदनों का कार्यकाल	- 83
(d)	राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन	- 88

उत्तर-(d) **UPPSC ACF/RFO 2021 Paper-II**

व्याख्या- सही सुमेलित है–

(प्रावधान)	(अनुच्छेद)
सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति	- 127
लोकसभा के अध्यक्ष	- 93
संसद के सदनों का कार्यकाल	- 83
राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन	- 86

Note:- जबकि अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार का प्रावधान करता है।

16. संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक अनुच्छेद उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष के पास एक निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा?

(a) अनुच्छेद 99 (b) अनुच्छेद 101
(c) अनुच्छेद 100 (d) अनुच्छेद 102

उत्तर-(c) UPPSC A.H.M. Officer 2021

व्याख्या- संविधान के अनुच्छेद 100 में उपबंधित किया गया है कि अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति मत बराबर होने की दशा में उसके पास एक निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

17. संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा?

(a) अनुच्छेद 99 (b) अनुच्छेद 103
(c) अनुच्छेद 100 (d) अनुच्छेद 102

उत्तर–(c) UPPCS (Pre.) Re-exam. G.S., 2015

व्याख्या– उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

18. निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है?

A. समानता का अधिकार – अनुच्छेद 14 – 18
B. शोषण के विरुद्ध अधिकार – अनुच्छेद 20 – 22
C. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार – अनुच्छेद 25 – 28
D. सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार – अनुच्छेद 29 – 30

उत्तर-(b) UPPSC GDC 2021

व्याख्या- सही सुमेलन है –
समानता का अधिकार – अनुच्छेद 14 – 18
शोषण के विरुद्ध अधिकार – अनुच्छेद 23 – 24
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार – अनुच्छेद 25 – 28
सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक
स्वतंत्रता का अधिकार – अनुच्छेद 29 – 30

19. निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है?

(a) अनुच्छेद 52 – राष्ट्रपति का निर्वाचन
(b) अनुच्छेद 51A – मौलिक कर्त्तव्य
(c) अनुच्छेद 154 – राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ
(d) अनुच्छेद 165 – राज्य का महाधिवक्ता

उत्तर-(a) UPPSC GDC 2021

व्याख्या- अनुच्छेद 52 – भारत का एक राष्ट्रपति होगा
अनुच्छेद 51 (A) – मौलिक कर्तव्य
अनुच्छेद 154 – राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ
अनुच्छेद 165 – राज्य का महाधिवक्ता
राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी उपबंध संविधान के अनुच्छेद 54 में वर्णित है।

20. भारतीय संविधान के किस भाग में संघ-राज्य सम्बन्ध है?

(a) भाग – V (b) भाग – VII
(c) भाग – VIII (d) भाग – XI

उत्तर-(d) UPPSC Poly. Lecturer 2021

व्याख्या- सही सुमेल इस प्रकार है–

संविधान के भाग -	वर्णित उपबन्ध
भाग (XI)	- संघ और राज्यों के बीच संबंध (अनुच्छेद 245 से 263 तक)
भाग (VIII)	- संघ राज्य क्षेत्र (अनुच्छेद 239-242तक)
भाग (V)	- संघ (अनुच्छेद 52-151 तक)
भाग (VII)	- प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य-सातवें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसित

21. निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है?

(a) अनु. 72 (b) अनु. 74
(c) अनु. 78 (d) अनु. 80

उत्तर-(a) UPPSC Poly. Lecturer 2021

व्याख्या- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-72 के तहत् राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गयी है।

22. निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन-सा एक भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार देता है?

(a) अनुच्छेद 68 (b) अनुच्छेद 70
(c) अनुच्छेद 72 (d) अनुच्छेद 73

उत्तर-(c) UPPSC ACF/RFO 2021 Paper-II

व्याख्या- उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

23. निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है?

(a) अनुच्छेद 322 (b) अनुच्छेद 324
(c) अनुच्छेद 352 (d) अनुच्छेद 361

उत्तर-(b) UPPSC Poly Lecturer 2021

व्याख्या- भारतीय संविधान के अनुच्छेद -324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य आयुक्तों से मिलाकर बना होता है। जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

24. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है?

(a) अनुच्छेद 243 K (b) अनुच्छेद 243 B
(c) अनुच्छेद 243 E (d) अनुच्छेद 243 F

उत्तर-(a) **UPPSC ACF/RFO 2021 Paper-II**

व्याख्या- भारतीय संविधान अनुच्छेद- 243K में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है।

25. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है।

(a) अनुच्छेद–252 (b) अनुच्छेद –249
(c) अनुच्छेद –250 (d) अनुच्छेद –253

उत्तर-(d) **UPPSC RO/ARO (Pre) 2021**

व्याख्या- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-253 के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यह व्यवस्था केन्द्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरा करने के योग्य बनाती है।

26. निम्नांकित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

(विषय)		**(सम्बन्धित अनुच्छेद)**
(a) न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण	-	अनुच्छेद 50
(b) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि	-	अनुच्छेद 46
(c) सहकारी सोसाइटी का संवर्धन	-	अनुच्छेद 43 A
(d) ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वयात्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना	-	अनुच्छेद 40

उत्तर-(c) **UPPSC (Pre) 2021**

व्याख्या– उचित सुमेलन है-

विषय		**सम्बन्धित अनुच्छेद**
न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण	-	अनुच्छेद - 50
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि	-	अनुच्छेद - 46
ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाईयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना	-	अनुच्छेद - 40

अनुच्छेद -43(A) उद्योगों के प्रबन्ध में कर्मकारों के भाग लेने के सम्बन्ध में है।

27. संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है?

(a) अनुच्छेद 43 (b) अनुच्छेद 43A
(c) अनुच्छेद 45 (d) अनुच्छेद 47

उत्तर–(b) **U.P. Lower (Pre.) G.S. 2009**

व्याख्या– उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

28. निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से सम्बन्धित है?

(a) अनुच्छेद 265 (b) अनुच्छेद 266
(c) अनुच्छेद 267 (d) अनुच्छेद 268

उत्तर-(c) **UPPSC (Pre) 2021**

व्याख्या– भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों को अपनी-अपनी 'आकस्मिक निधियां' स्थापित करने का प्राधिकार देता है। आकस्मिकता निधि संघ या राज्य में राष्ट्रपति या राज्यपाल के हाथ में रखी जाती है। ताकि वह अप्रत्याशित व्यय के पूर्ति के वास्ते तब तक के अग्रिम धन दे सके जब तक कि संसद या विधानमण्डल उसे प्राधिकृत नहीं कर देते।

29. निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?

संविधान की अनुसूची	**प्रावधान**
(a) तीसरी अनुसूची	शपथ का फार्म
(b) सातवीं अनुसूची	तीन विधायी सूचियां
(c) आठवीं अनुसूची	भाषाएं
(d) पहली अनुसूची	पंचायत

उत्तर-(d) **UP PSC Vetting Officer 2020**

व्याख्या–

संविधान की अनुसूची	**प्रावधान**
(a) तीसरी अनुसूची	शपथ का फार्म
(b) सातवीं अनुसूची	तीन विधायी सूचियां
(c) आठवीं अनुसूची	भाषाएं
(d) पहली अनुसूची	राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सूची

पंचायत का प्रावधान संविधान के ग्यारहवीं (11) अनुसूची में वर्णित हैं।

30. निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है?

(a) सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची
(b) जनगणना संघ सूची
(c) राज्य सभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची
(d) दलबदल विरोध दसवीं अनुसूची

उत्तर–(c) **UPPCS Pre-2019**

व्याख्या– भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। जिसमें चौथी अनुसूची में 'राज्यसभा में सीटो का बँटवारा, दसवीं अनुसूची दल बदल से सम्बंधित है। सातवीं अनुसूची में केन्द्र व राज्य के बीच शक्तियों का बँटवारा किया गया है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, राज्य सूची से व जनगणना, संघ सूची से सम्बंधित है।'

31. शिक्षा एक विधि-विषय के रूप में सम्मिलित है:

(a) संघीय सूची में (b) राज्य सूची में
(c) समवर्ती सूची में (d) शेष शक्ति सूची में

उत्तर-(c) **UPPSC-DIET 2014**

व्याख्या– 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, इससे पहले वह राज्यसूची का विषय था।

32. भारत की संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं?

(a) 44 (b) 47
(c) 67 (d) 97

उत्तर-(d) **UPPSC AE- 2013**

व्याख्या– अनुसूची-VII में केन्द्र राज्य संबंधों के आलोक में तीन सूचियों संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का उपबंध किया गया है। भारत की संघ सूची में 97 (वर्तमान में 100) विषय सम्मिलित जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची में कुल 66 विषय (वर्तमान में 61) व समवर्ती सूची में कुल 47 विषय (वर्तमान में 52) है।

33. भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में तीन विधा सूचियों का प्रावधान है-

(a) VI (b) VII
(c) VIII (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर-(b) **UPPSC RO/ARO (Mains) 2021**

व्याख्या- उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

34. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित (रेगुलेट) करने की शक्ति प्रदान करता है?

(a) अनुच्छेद 8 (b) अनुच्छेद 9
(c) अनुच्छेद 10 (d) अनुच्छेद 11

उत्तर–(d) **(UPPCS (Pre) Opt. Spl. Pol. Science 2008)**

व्याख्या–भारतीय संविधान को अनु. 11 को संसद को नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके लिए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया है।

35. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद/अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई?

(a) अनुच्छेद 14 (b) अनुच्छेद 14 तथा 15
(c) अनुच्छेद 14, 15 तथा 16 (d) अनुच्छेद 14 तथा 16

उत्तर–(d) **UPPCS (Pre.) G.S.Spl., 2004**

व्याख्या– यद्यपि 'समान कार्य के लिए समान वेतन' अनु. 39(d) में उल्लिखित नीति निदेशक तत्व है तथापि सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ (1982) के मामले में यह निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त 'समाजवाद' शब्द और अनु. 39(d) के परिप्रेक्ष्य में अनु. 14 और अनु. 16 को पढ़ने से 'समान कार्य के लिए समान वेतन' का सिद्धांत प्राप्त होता है।

36. निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

(a) मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम पर रोक - अनुच्छेद 24
(b) गैर-कानूनी निरोध से संरक्षण - अनुच्छेद 22
(c) प्राथमिक शिक्षा का अधिकार - अनुच्छेद 21A
(d) लोक नियोजन में समानता - अनुच्छेद 16

उत्तर-(a) **UP PSC ACF/RFO (Mains) 2018 Paper II**

व्याख्या–

मौलिक अधिकार	**संबंधित अनुच्छेद**
मानव के दुर्व्यापार तथा बलात श्रम पर रोक	अनुच्छेद 23
गैर कानूनी निरोध से संरक्षण	अनुच्छेद 22
प्राथमिक शिक्षा का अधिकार	अनुच्छेद 21A
लोक नियोजन में समानता	अनुच्छेद 16

37. भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से सम्बन्धित अनुच्छेद है –

(a) अनुच्छेद 15 (b) अनुच्छेद 16
(c) अनुच्छेद 17 (d) अनुच्छेद 18

उत्तर–(c) **UPPCS (Pre.) G.S.Spl., 2004**
UPPCS (Pre.) G.S., 1994
UP PSC RO/ARO (Pre) 2017

व्याख्या – संविधान के अनुच्छेद-17 के अंतर्गत छुआछूत का उन्मूलन कर दिया गया है और इसे भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। संसद में सन् 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया था।

38. निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है?

(a) एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता
(b) कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न
(c) पानी की गुणवत्ता को दूषित करना
(d) मृत्युदण्ड

उत्तर–(d) **UPPCS (Pre) 2017**

व्याख्या– संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में मृत्यु दंड नहीं आता है। चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता परमानंद बनाम भारत संघ (1998) में, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (विशाखा मामले में अनुच्छेद 14, 19 व 21) तथा स्वच्छ जल संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल है।

39. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का सम्बन्ध है–

(a) समानता के अधिकार से (b) सम्पत्ति के अधिकार से
(c) धर्म की स्वतन्त्रता से (d) अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से

उत्तर – (c) **UPPCS (Pre.) G.S., 1996**

व्याख्या–अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता से सम्बन्धित है।

40. किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राविधान है?

(a) अनुच्छेद 20 में (b) अनुच्छेद 21 में
(c) अनुच्छेद 22 में (d) अनुच्छेद 74 में

उत्तर–(a) **U.P. Lower (Pre.) Spl. G.S. 2004**

व्याख्या–अनु. 20-अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण– इस अनु. में तीन बातें उल्लिखित हैं

(i) कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय, जो अपराध के रूप में आरोपित हैं, किसी प्रवृत्त विधि

का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी।

(ii) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दण्डित नहीं किया जाएगा।

(iii) किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

41. ''किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दण्डित नहीं किया जाएगा'' अपराधों के लिए दोषसिद्धि के सम्बन्ध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है?

(a) अनुच्छेद 19 (b) अनुच्छेद 20

(c) अनुच्छेद 21 (d) अनुच्छेद 22

उत्तर–(b) **UPUDA/LDA Special (Mains) G.S., 2010**

व्याख्या– उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

42. भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गयी है कि सभी, अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा?

(a) अनुच्छेद 28 (b) अनुच्छेद 29

(c) अनुच्छेद 30 (d) अनुच्छेद 31

उत्तर–(c) **UPPCS (Mains) G.S. IInd 2017**

UPPCS (Pre.) G.S., 1997

व्याख्या– अनुच्छेद-30–खण्ड (1) के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

43. भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से सम्बन्धित है?

(a) अनुच्छेद 17 (b) अनुच्छेद 19

(c) अनुच्छेद 23 (d) अनुच्छेद 24

उत्तर– (d) **UPPCS (Mains) G.S. IInd 2017**

व्याख्या– अनुच्छेद- 23 एवं 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से सम्बन्धित है।

अनुच्छेद- 23 (1)– के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।

अनुच्छेद-24– के अनुसार ''चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।

44. भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है?

(a) अनुच्छेद 19 (b) अनुच्छेद 17

(c) अनुच्छेद 23 (d) अनुच्छेद 24

उत्तर–(d) **UPUDA/LDA Special (Pre) G.S., 2010**

व्याख्या – उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

45. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है –

(a) समान सिविल संहिता के सम्बन्ध में

(b) ग्राम पंचायतों के संगठन के सम्बन्ध में

(c) नगरपालिकाओं के गठन के सम्बन्ध में

(d) कर्मकारों के लिये निर्वाह योग्य मजदूरी के सम्बन्ध में

उत्तर–(b) **UPPCS (Pre) G.S., 2015**

UPPCS (Pre) G.S., 2014

UPPSC Food & Sanitary Inspector Exam, 2013

व्याख्या– अनुच्छेद 40 (भाग-4, नीति निदेशक तत्व) में उपबंधित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।

46. निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

(a) धन विधेयक - अनुच्छेद 110

(b) राज्यों में राष्ट्रपति शासन - अनुच्छेद 356

(c) न्यायिक पुनर्निरीक्षण - अनुच्छेद 243

(d) समान नागरिक संहिता - अनुच्छेद 44

उत्तर– (c) **UPPSC ACF (Pre) 2017**

व्याख्या– सही सुमेल निम्न है-

अनुच्छेद-110 – धन विधेयक

अनुच्छेद-356 – राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा के उपबंध

अनुच्छेद-243 – स्थानीय स्वशासन से संबंधित

अनुच्छेद-44 – नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता

अनुच्छेद-137 – निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन

अतः स्पष्ट है कि विकल्प (c) सही नहीं है।

47. सूची-I सूची-II को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए-

सूची-I (संविधान के अनुच्छेद)	**सूची-II (विषय)**
A. अनुच्छेद 40	1. गांव पंचायत का गठन
B. अनुच्छेद 41	2. काम करने का अधिकार
C. अनुच्छेद 44	3. समान नागरिक संहिता
D. अनुच्छेद 48	4. कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था

कूट-

	A	**B**	**C**	**D**
(a)	1	2	3	4
(b)	2	3	1	4
(c)	1	3	4	2
(d)	3	2	4	1

उत्तर–(a) **UPUDA/LDA (Pre.) G.S., 2001**

UPUDA/LDA (Pre.) G.S., 2006

व्याख्या –

ग्राम पंचायत का गठन - अनुच्छेद 40

काम करने का अधिकार - अनुच्छेद 41

समान नागरिक संहिता - अनुच्छेद 44

कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था - अनुच्छेद 48

48. निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है?

(a) अनुच्छेद 39A – समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता
(b) अनुच्छेद 40 – ग्राम पंचायतों का संगठन
(c) अनुच्छेद 44 – समान नागरिक संहिता
(d) अनुच्छेद 48 – न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण

उत्तर–(d) **UPPCS (Pre) G.S., 2013**

व्याख्या – कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण का उल्लेख संविधान के अनु. 50 में हैं।

49. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से सम्बन्धित है?

(a) अनुच्छेद 380 (b) अनुच्छेद 312
(c) अनुच्छेद 60 (d) अनुच्छेद 51

उत्तर–(d) **UPPCS (Pre.) G.S., 2016**
UPPSC Asstt. Forest Conservator Exam, 2015

व्याख्या – भाग-4 (राज्य के नीति निदेशक तत्व) के अनुच्छेद-51 के अनुसार राज्य– (a) अंतर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि, (b) राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत एवं सम्मानपूर्ण संबंधों को अक्षुण्ण रखने, (c) अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान वार्ता एवं मध्यस्थता द्वारा करने तथा (d) राष्ट्रों की पारस्परिक व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय संधियों या कानूनों के प्रति सम्मान की भावना बढ़ाने का प्रयास करेगा।

50. संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है?

(a) अनुच्छेद 360 (b) अनुच्छेद 123
(c) अनुच्छेद 200 (d) अनुच्छेद 356

उत्तर-(b) **UPPCS (Mains) G.S. IInd Paper, 2016**

व्याख्या-संविधान के अनु. 123 में उल्लिखित है कि संसद के विश्रांतिकाल में राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा।

51. संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जाँच करना प्रतिबंधित किया गया है?

(a) अनुच्छेद 127 (b) अनुच्छेद 122
(c) अनुच्छेद 126 (d) अनुच्छेद 139

उत्तर–(b) **UPUDA/LDA Special (Mains) G.S., 2010**

व्याख्या–अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जाँच न किये जाने का विवरण है।

52. निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अन्तर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है?

(a) अनुच्छेद 104 (b) अनुच्छेद 105
(c) अनुच्छेद 82 (b) अनुच्छेद 117

उत्तर–(b) **UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 2008**

व्याख्या – अनुच्छेद 105, संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है।

53. भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है –

(a) 138 (b) 140
(c) 142 (d) 146

उत्तर–(c) **UPPCS (Mains) G.S. IInd 2014**

व्याख्या–सुधारात्मक याचिका की अवधारणा संविधान के अनुच्छेद 142 के विश्लेषण से निकलती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहली बार रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा (2002) के मामले में सुधारात्मक याचिका का प्रयोग किया गया था। यह प्राकृतिक न्याय के हनन के मामले में आता है।

54. राज्यों में विधान परिषद् के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है?

(a) अनुच्छेद 368 (b) अनुच्छेद 69
(c) अनुच्छेद 269 (d) अनुच्छेद 169

उत्तर-(d) **UPPCS (Mains) G.S. IInd Paper 2007**

व्याख्या– संविधान के अनुच्छेद 169 में विधानपरिषद् के सृजन व उत्सादन के सम्बन्ध में उपबन्ध किया गया है।

55. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 सम्बन्धित है –

(a) राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से
(b) लोकसभा के विघटन से
(c) संसद की प्रशासनिक शक्तियों से
(d) राज्य सूची के विषयों के सम्बन्ध में संसद की विधायी शक्तियों से

उत्तर : (d) **UPPCS (Mains) G.S. IInd 2009, 2012, 2017**
UPPCS (Pre) Opt. Pol. Science 1995

व्याख्या – अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्य सभा द्वारा ऐसे प्रस्ताव पास कर दिये जाने पर संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लागू होता है, लेकिन यदि राज्य सभा चाहे तो हर बार इसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

56. राज्य सभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद–249 के अन्तर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, प्रवृत्त रहेगा।

(a) छह मास से अधिक नहीं(b) दो वर्ष से अधिक नहीं
(c) एक वर्ष से अधिक नहीं(d) असीमित काल तक

उत्तर–(c) **UPPCS (Pre) 2017**

व्याख्या– उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

57. संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गयी है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा-

(a) अनुच्छेद 349 (b) अनुच्छेद 350
(c) अनुच्छेद 350(क) (d) अनुच्छेद 351

उत्तर—(c) **UPPCS (Pre.) G.S., 2002**
UP Lower (Pre) G.S., 2002